साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
+91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 17 | अंक 21 | प्रति सोमवार इंदौर, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 | पृष्ठ 8 | मूल्य 5/- रुपए

पूंजीपति मित्रों के मोटे फायदे और शॉपिंग माल चलाने

कोरोना वापसीः शीत ऋतु में सर्दी-खांसी-जुकाम स्वाभाविक

सारे छोटे उद्योगों दुकानदारों ठेले पद मार्गों के विक्रेताओं को खत्म करने का षड्यंत्र

पिछले 10 वर्षों में जब से पूंजीपतियों के रख ले और उसके सारे पर नाचने वाले मोदी ने सत्ता संभाली तब से अभी तक सारा खेल सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने से लेकरउनके मोटे फायदे के लिए छोटे व्यवसाय में दुकानदारों कृषि बाजारों मंडियों को खत्म करने का न केवल प्रत्यक्ष षड़तंत्र किये गये वरन विश्व घातक संगठन के इशारे व मोटे धन के लिए पर देसी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मोटे फायदे के लिए लक्षित कर कार्य ही किए जाते रहे हैं

अप्रत्यक्ष षड्यंत्रों में जनता को भ्रमित करने व बर्बाद करने सफाई कैशलेस नोटबंदी जीएसटी कोरोना जैसे पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाले और बार-बार करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर बर्बाद करने के साथ पूरे देश की जनता का डाटा इकट्ठा करने जमा धन और पूंजी को बाहर निकालने उथल-पुथल कर हैरान परेशान कर बेरोजगार बनाने वाले कांड ही किये हैं। 22 मार्च 2020 से कोरोना का तांडव का उपदेश भी यही था ताकि बीमारी के नाम पर लोगों को घर में बंद कर उनके व्यवसाय

में नियमित खर्चों को चलते भारी घाटा हो और वह सारे के सारे बंद हो जाएं जबकि हर बदलते मौसम में मानव सभ्यता की जागृति से लेकर अभी तक सर्दी खांसी जुकाम न केवल मनुष्य को वरन हर प्राणी को तापमान के अचानक ऊपर नीचे होने से होता आया है नया कुछ भी नहीं हुआ था। फिर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हमारे देश के सनातन धर्म के पौराणिक महत्वपूर्ण चार वेदों में से एक आयुर्वेद यथार्थ में पूरा मानव जीवन का चिकित्सा विज्ञान वह प्रकृति के अनुकूल प्रकृति के साथ जीने की कला सिखाता है जो आज भी आधुनिकता का राग अलापने वाले जालसाजी पूर्ण एलोपैथी पर भारी पड़ता है। जिसका प्रचार प्रसारपिछले 10 सालों में सनातन का राग अलापने वाली भारतीय जनता पार्टी पितृ संस्था राष्ट्रीय सेवक बनाम पूंजीपति सेवा संघ जो अपने सेवकों और जनता को छद्म राष्ट्रीयता, धर्म, पौराणिक संस्कृति, संस्कारों की घुट्टी पिलाकर भ्रमित करती है ने कभी नहीं किया। आखिर हमारे आयुर्वेद को जिसकी औषधीयों के रूप में हमारे दैनिक जीवन के फल फूल अनाज दलहन तिलहन के साथ हमारे घरों की रसोई में रखें सारे मसाले जो हमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खिलाये जा रहे पैकेज्ड फूड जिसमें कीटनाशक व अन्य घातक रसायन होते हैं। जैसे विषैले बीमारी फैलाने बढ़ाने गंभीर रोगों का शिकार बना अपनी महंगी लागत की शल्य चिकित्सा व रासायनिक औषधीयां बैंचने का षड्यंत्र करते हैं। इन सब से हमारे घरेलू मसाले यथा लहसुन अदरक काली पीली सफेद कच्ची हल्दी लाल काली हरी मिर्ची जीरा राई धनिया दालचीनी लौंग इलायची जायफल आदि सब्जियां प्याज टमाटर लौकी पपीता कद्दू आदि बीमारियों से बचाती हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है, कि 22 मार्च 2020 के पहले सर्दी खांसी जन्म होने वाली 20 से ज्यादा बीमारियां कोरोना के बाद कहां गायब हो गई

(शेष पेज 2 पर)

क्या आतंकवादियों का उपयोग भी चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है

वाचाल के आतंक को खत्म करने के दावे खोखले

सत्ता में आने से पहले आतंकवाद के विरोध में वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी बड़ी लंबी चौड़ी हांकते फांकते थे। पर सत्ता संभालने के बाद और 370 खत्म करने के बाद में भी आतंकवाद ना तो खत्म हुआ नाकाम हुआ जिसकी कुछ बड़े अक्षरों की कटिंग और सूचना यहां चिपका रहा हूं।

स्वयं सरकार ने लोकसभा में स्वीकार किया आतंकवाद से हर साल मौतें हुई

दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से प्राप्त ठाकुर के अनुसार वहां पर भी सरकार स्वयं आतंकवादियों को पालती है। जानबूझकर देश के लोगों में दहशत पैदा करने, अपने सैनिकों पर आतंकवादी हमले करवाने के लिए गोपनीयता के साथ छूट दी जाती है। ताकि मीडिया सरकार के नाकामियों भ्रष्टाचार को छुपाने देश और देश की जनता का ध्यान आतंकवादी हम लोग से मरे लोगों के बारे में सहानुभूति खट्टी करने के काम आए जबकि आतंकवादियों को सफाई करने के नाम परवहां की पुलिस और मिलिट्री जो छोटे-छोटे अपराधों में बंद कैदी होते हैं या जिनकी छोटे-मोटे अपराध होते हैं उनको जंगलों में दौड़ा कर गोली मारकर आतंकवादियों को सफाई का नाम दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के लोगों का यह आप और उसकी सत्यता जो वहां के लोग जानते हैं बहुत पुराने हो चुके हैं जो पिछले साल के मोदी शासन काल में और बढ़ गए।

घोर लालची मानसिकता देश के संस्थानों से जनता तक को कर रही बर्बाद

गूगल-माइक्रोसॉफ्ट चीन कर रहे भारतीय डाटा का दुरुपयोग

5000 से ज्यादा एप कर रहे डाटा चोरी, आईटी सेल भी कर रहा दुरुपयोग

पूरी दुनिया की 780 करोड़ आबादी से लेकर सभी राष्ट्रो की सरकारों के सभी नागरिक विभागों से लेकर सी ज्ञान विज्ञान आदि सब कुछ गोपनीय सूचना तंत्र भी अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट व गूगल के सूचना तंत्र के मकड़ जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है। बेशक रूस और चीन ने अपने तंत्र को काफी हद तक इन कंपनियों मकड़जाल से मुक्त कर रखा है। बेशकइन दोनों कंपनियों ने दुनिया के देशों की सरकारों को धन बांट कर वहां के सार्वजनिक धन को लूट मोटी कमाई कर रही है बेशक हमारा देश उल्टे ही जनता की, नेताओं की, सरकारी विभागों बैंकों बीमा कंपनियों से लेकर सुरक्षा व रक्षा विभाग तक का सारा डाटा गूगल माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से क्योंकि सारे सरकारी विभागोंके के सुरक्षा व रक्षा संस्थानों के कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े होने के कारण वैसे भी वह सूचनायें उनके पास पहुंचती हैं। जिसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग चीनी मोबाइलों और उसके इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल टावर मैं लगे उपकरणों से लेकर वृहत स्तर भारत के निजी व सरकारी संस्थानों से लेकर और रक्षा संस्थानों तक में उपयोग किया जा रहे उपकरणों के साथ इंटरनेट साइटों का उपयोग करने के कारण चीन के आईटी एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत सब

चीन में संग्रहित होता है पर भारत सरकार के वर्तमान प्रधानमंत्री जाहिल मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए चार बार और प्रधानमंत्री रहते हुए तीन बार चीन की यात्रा की और उसे मोटा पैसा लेकर चीन को हर क्षेत्र में भारत के साथ न केवल डाटा चोरी वह अन्य प्रकार के राष्ट्र के संस्थानों व जनता के साथ समंकों के संकलन का खेल करने की खुली छूट दे रखी है। इसलिए वह न केवल भारत के बल्कि दुनिया के अधिकांश देश जिसमें इंग्लैंड अमेरिका फ्रांस जर्मनी कनाडा ऑस्ट्रेलिया अग्रिम पंक्ति के देशों कीजनता किस लेकर सरकारी विभागों की विभिन्न माध्यमों से जासूसी करता रहता है पर उसका सार्वजनिक प्रदर्शन उपयोग दुरुपयोग और सदुपयोग सामने न आने के कारण इस प्रकार की सार्वजनिक बदनामी से बचा हुआ है। अमेरिका जैसे देश उसकी अनेकों इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के माध्यम से की जा रही जासूसी के पर कुछ गोपनीय प्रकरणों के सामने आने और उसके हस्तक्षेप के कारण प्रतिबंध लगाने की मांगवर्षों से करते आ रहे हैं और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिसमें मोबाइल स्मार्ट टीवी कंप्यूटर स्पेयर्स से लेकर अनेकों अन्य प्रकार के विद्युत उपकरणों यथा पंखे लाइट बल्ब मोटर आदि से लेकर बच्चों के खिलौने स्वचलित वाहनों बैटरीवाली सैकड़ों उपकरणों के माध्यम से जो सस्ते होने के कारण अमेरिका इंग्लैंड जैसे यूरोपिय देशों में भारी मात्रा में निर्यात किए जाने वाले सामानों के माध्यम से भी जासूसी करता है।

भारत के अधिकांश विभाग न केवल गूगल के जीमेल गूगल मीट गूगल शीट गूगल कॉन्फ्रेंस गूगल सर्च इंजन का भारी मात्रा में उपयोग करने के कारण वह सारी जानकारीन केवल गूगल के पास इकट्ठा होती है पर वही जानकारी हैकर्स द्वारा चुराने व बस का दुरुपयोग करने के लाखों मामले हर वर्ष सामने आ रहे हैं (शेष पेज 3 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

20 साल पुराना ढर्रा बदलो

प्रदेश में सत्ता में मुख्यमंत्री का बदलाव होने से यथार्थ में पूरी सत्ता के प्रशासनिक संचालन के ढर्रे को पंचायत से लेकर हर विभाग के मंत्रालयों तक बदल जाना चाहिए। बेशक यह काम एक दिन में तो नहीं होगा परंतु बदलाव की शुरुआत शीर्ष स्तर पर जमे घोर धूर्त मक्कार जालसाज भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारियों विशेष रूप से जो पुरस्कृत आइएएस राज्य प्रशासनिक सेवा में भ्रष्टाचार से कमाये मोटा धन खर्च कर पदोन्नति के बहाने भारतीय सेवा अधिकारी सेवा में पुष्कृत हुए हैं वे अधिकांश जिलों में जिलों के शीर्ष पद जिलाधीश और संभाग के संभाग आयुक्त बनाकर बैठा दिए गए हैं। जहां पर सीधे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर आइएएस बनकर आए हैं। पद के हिसाब से पदस्थ किया जाना चाहिए। क्योंकि जो अधिकारी राज्य प्रशस्तिक सेवा में चुनकर आए थे और तहसीलदार सहायक उप जिलाधीश के पदों पर वर्षो तक काम कर जिन्होंने अपने पदों का भारी दुरुपयोग कर भू माफिया कानूनी माफियाओं राजस्ववी अनुच्छेद में भारी उल्टे सीधे फैसला कर और विभिन्न प्रकार के विभागों में काम करते हुए और नियंत्रित करते हुए मोटी कमाई की। इस भ्रष्टाचार के खेल को चाहे वह खनिज आबकारी राजस्व का खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ग्रामीण विकास आदि की शासन की विभिन्न योजनाओं को पूरा करने ग्रामीण विकास विभाग स्वास्थ्य विभाग दंडाधिकारी विभाग को राज्य प्रशासनिक सेवा के पदों पर तहसील विकास खंडों में विभिन्न पदों पर बैठ वह जिम्मेदारी संभाली और नीचे के प्रशासनिक स्तर से कारगुजारियां जालसाजियां करते हुए उच्च प्रशासनिक स्तर तक पहुंचकर वही कारगुजारियां भ्रष्टाचार कर मोटा पैसा इकट्ठा करते हैं और उसी मोटे धन से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं को धन बांट कर आसानी से भारतीय प्रशासनिक सेवा के पद पर आरूढ़ हो यही खेल वह पुनः अच्छे पदों को बैठने के लिए मंत्री व मुख्यमंत्री को बांट वह जिलों को रॉयल्टी व मासिक किस्तों पर हथिया जिलों के कलेक्टर संभागीय आयुक्त बनकर भी वहां मोटी कमाई करते हैं। बाद में ऐसी नीति का प्रयोग करते हुए वह राज्य के बड़े कमाई वाले मंत्रालय में बैठकर नियम कानून की धज्जियां बिखेरते बहुराष्ट्रीय कंपनी के सारे पर नाच कर एक तरफदलाली कर स्वयं के साथ अपने मंत्रियों और मुख्यमंत्री की भी मोटी कमाई करते हैं जैसा कि मनीष सिंह ने पिछले 20 सालों में करके वह शिवराज सिंह चौहान का खास से पैसा लहर बन गया था तो नए मुख्यमंत्री को चाहिए की वह तत्काल सारे प्रमोटिंग राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उच्च पदों से हटाकर उनको सहायक या अतिरिक्त सचिव के रूप में ही मंत्रालय में पदस्थ करें। यही सबसे बड़ा कारण था कि ऐसेभारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के रूप में बैठे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियोंनेप्रदेश की राजस्व कीपूरी व्यवस्था का भट्टा बैठा दिया और आज हालात यह हैकी उल्टी सीधी बड़ी-बड़ी योजनाओं में अनावश्यक रूप से धन खर्च करप्रदेश के खर्चो को चलाने के लिए लगातार बाजार सिक्का उठाया जाता रहा जो वर्तमान में 385000 करोड़ तक पहुंच गया और पुन: वही सलाह मुख्यमंत्री को देकर 2000 करोड रुपए का कर्ज फिर से बाजार से उठाया जा रहा है आखिरी क्यों जो सीधे भारतीय प्रशासनिक सेवा के ईमानदार अधिकारियों को राज्य के वित्त प्रबंधन बजट नियंत्रण आदि मंत्रालय में सेवाएं लेकर प्रदेश की सबसे पहली आवश्यकता वित्त प्रबंधन है उसके लिए नए मुख्यमंत्री को चाहिए की पुराने सारे प्रशासनिक ढांचे को बदलें और राज्य के प्रशासन में उच्च शिक्षित समझदार सीधे भर्ती किए गए प्रशासनिक सेवा के ईमानदार अधिकारियों को राजस्व संग्रहण हेतु जिलों के कलेक्टर व संभागों के आयुक्त के रूप में पदस्थ करने के साथ सभी कार्य विभागों में जिसमें लोक निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय जल संसाधन ग्रामीण विकास कृषि में पदस्थ आयुक्त और प्रधान सचिवों को तत्काल बदलकर अतिरिक्त चल रही योजना परियोजनाओं का खर्च करना रोका जाए केवल रखरखाव के कार्यो को संपन्न किया जाए ताकि प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को कम करने के साथवित्तीय स्थिति को नियंत्रित किया जा सके इसको नए मुख्यमंत्री को समझना होगा।

आओ तुम्हे बताता हूँ 56 का सीना क्या होता है

बात बहुत पुरानी नही हैं। चीन एक बार फिर आंख दिखा रहा था, 1962 गिना रहा था। उसे 1967 याद दिलाने की जरूरत थी। यह 1986 था और भारत की ऊंची गद्दी पर इस वक्त बिंदास बन्दा बैठा था।

नाम था राजीव ..

सीमा पर दो कदम आगे, एक कदम पीछे होना चीन की नीति रही है। छल कपट, मीठी जुबान, सेना आगे बढाकर मानसिक दबाव डालना उसका तरीका रहा है।

इसके पीछे सन 49 से ड्रेगन की एक ही मोटिव रहा है- अक्साई चिन को बचाना।

अक्साई चिन से गुजरता हाइवे, काशगर- जिनजियांग और बीजिंग को जोड़ने वाली गर्भनाल है। CPEC और पाकिस्तान जाने वाला कराकोरम हाइवे भी यहीं से निकला है।

चाऊ ने 59 में यह प्रस्ताव दिया- नेफा (अरुणाचल) तुम्हारा मान लेते है, अक्साई चिन हमारा मान लो।

नेहरू नरम थे, मगर संसद और मीडिया में आलोचना के बाद प्रस्ताव ठुकरा दिया।

विदेशमंत्री बाजपेयी को भी यही प्रस्ताव मिला, मगर कुछ कर पाते कि सरकार चली गयी। दोबारा सरकार में आयी इंदिरा से चीन ने ये बात कहने की हिम्मत ही नही की।

पर अब इंदिरा नही थी, राजीव का दौर था। यही प्रस्ताव फिर आया।

उन्होंने ठुकरा दिया गया, तो चीन ने नेफा में गतिविधियां बढ़ा दी। रोज उनका जमावड़ा सीमा पर आगे बढ़ आता, हमे पेट्रोलिंग से रोकता।

उस वक्त डर के मारे कांपते हुए प्रधानमंत्री ने देश से ऐसा नही कहा- 'न कोई घुसा है, न घुस आया है'

नही, वो राजीव थे तो ऐसा नही कहा।

उन्होंने फोन उठाया, आदेश दिया।

पूर्वी कमान के मेजर जनरल जिमी ने आदेश का पालन करने के लिए खच्चर मांगे।

सेनाध्यक्ष सुंदरजी से 1200 खच्चर मांगे। उस बन्दे के सेनापति से, जो भारत को कम्पूटर युग में ले जा रहा था, खच्चर मांगे गए।

चीनी सीमा पर दोनों पक्ष हैवी इक्विपमेंट्स और आर्टिलरी इस्तेमाल नही करते। यही आपसी समझौते हैं। तो खच्चर मांगे गए।

खच्चर नही दिए गए।

बिल्कुल नही दिए गए

रशियन मेड हैवी लिफ्ट हेलीकाप्टर दिए गए। उसमे भरे बम, बंदूकें, बड़ी बड़ी गन्स, फौजी, राशन, फोर्टीफिकेशन के लिए समान

और उड़ चले तवांग से 90 किलोमीटर आगे उन पहाड़ियों में, जहां चीन हमे पेट्रोलिंग से रोकता था। फौजें अड़ा देता था।

मिशन साफ था, उन पहाड़ियों पर कब्जा करना जो मैकमैहन लाइन के अनुसार हमारी थी।

वी शैल टेक व्हाट वी क्लेम !!!

एयरलिफ्ट की तारीख 18 से 20 अक्टूबर। डेट इसलिए सलेक्ट की, क्योंकि यही 1962 में चीनी हमले की तारीख थी।

फिल्मी दुनिया मे इसे स्टाइल से बदला लेना कहते हैं।

चीनी फ़ौज को इस स्टाइल की हिम्मत की उम्मीद नही थी। एकाएक बड़ा इलाका हाथ से निकल गया। बगैर एक भी कैजुअल्टी के भारत को जीत मिली, और चीन को मात।

चीन बौखलाया, कूटनीति गर्म होने लगी। चीनी नेताओं ने लाल लाल आंख दिखानी शुरू की डिएस्केलेट करने को दबाव आया।

राजीव मुस्कुराए।

एक चुम्बन, पूर्व की ओर उछालकर कहा

- जो करना हो करो ।

और नेफा का नाम अरुणाचल हुआ। उगते सूर्य का प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया!!

दूसरी मात!!

तो अब नेफा के लोग भारतवासी थे। विद फुल इंडियन पासपोर्ट। अपनी स्टेट गवरमेंट बनाकर भारत के संविधान की शपथ ले रहे थे।

और बोलो..

भारत के इस सैनिक ऑपरेशन को जनरल सुंदरजी की भूमिका वही थी, जो 71 में सैम मानेकशॉ की थी।

जनरल जिम्मी ने वही काम किया थे, जो जनरल जैकब ने 71 में किया।

इस देश की सेना में सैम, सुंदरजी, हमीद, शैतान सिंह, सोमनाथ शर्मा, अर्जन सिंह, जैकब और जगजीत सिंह अरोड़ा तब भी थे, और आज भी हैं।

नही है तो देश की ऊंची कुर्सी पर इंदिरा जैसी ऊंची नाक, या राजीव जैसी दृढ़ मुस्कान।

56 इंच की पिलपिली छाती पर चीनी कालोनी बसा रहे हैं। नेता 'ङकोई आया न-कोई घुसा' का राग अलाप रहे हैं।

1962 और 1959 के किस्से निकालकर नेहरू की अचकन में मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।

ब्लडी कावर्ड पिपुल .. !!

किसी सरकार को जब चीन का डर सताए, तो पूरी कैबिनेट को बैठकर सन 86 के 'ऑपरेशन फाल्कन' की कहानी सुननी चाहिये।

इसलिए कि शौर्य गाथाओं को सुनने से दिल का डर घटता है, हिम्मत बंधती हैं।

पर क्या ये किस्से 56 इंच की पिलपिली छातियों में हिम्मत भर सकते है?

पता कीजिये, और यह किस्सा कॉपी कर इस सरकार के प्यादों और भक्तों तक भेजिये। उन्हें बताइये कि 56 इंच का सीना ऐसा होता है।

कोरोना वापसीः शीत ऋतु में सर्दी-खांसी-जुकाम स्वाभाविक

पेज 1 का शेष

जबकि उन सभी बीमारियों के जिसमें शीत ऋतु व मच्छरों के काटने से होने वाले डेंगू फ्लू वायरल मलेरिया के साथ संक्रामक मानी जाने वाली इनफ्लुएंजा निमोनिया जिनके अलग-अलग 10 से ज्यादा प्रकार की अलग-अलग जांच अलग-अलग औषधीयां होती थी, की बाद में भी काली खांसी अस्थमा स्वांस टीवी जैसी बीमारियां भी सर्दी खांसी जुकाम के बाद में ही बड़ा गंभीर रूप लेती थी। जो आयुर्वेद, यूनानी होम्योपैथी के साथ एलोपैथी में भी वर्णित है।

आखिर सारी कहां खो गई? जो छद्म षड्यंत्रकारी कोरोना के घातक रूप में जेएन वन व अन्य प्रकार के नाम देकर जनता कोमुदितवी दृश्य मीडिया के माध्यम से लगातार जनता को डराया जा रहा हैतो क्या बोलूं देश पूर्वी की तरह अपने पूंजीपति मित्रों का फायदा करवा नहीं है यदि जनता को स्वस्थ रखना है तोउसके घर पर रख मसाले के सदुपयोग और उसके मूल्यांकन के साथ उसका औषधि प्रयोग करने की जानकारी दी जानी चाहिए ताकि लोग सर्दी खांसी जुकाम सेबदलते मौसम में अपनी रक्षा करना सीख सकें ना कि उनको डरा धमका कर मुंह पर मास्क बनवा कर अस्पतालों में भर्ती करने का संयंत्र किया जा रहा हैताकि न केवलनिजी चिकित्सकों डॉक्टरों की मोटी कमाई हो सके वर्णन बेरोजगार भट्टी जनता इसके कुछ चक्कर में फंसकर अपने आप को बर्बाद करते रहने का दंश भोगती रहे। जिसे तत्कालबंद किया जाना चाहिए समाचार पत्रों को भीजनता को इस बदलते मौसम में सर्दी खांसी जुकाम से सुरक्षित रहने के लिएघरों में रखे मसाले के औषधि प्रयोग बताए जाने चाहिए ताकि वहइन सब स्टूडेंट में बचने की अपेक्षाकोरोना के तांडव से अपने आप को सुरक्षित कर सके।

जहां तक लोगों के इस बीमारी से करने का सवाल है तो 140 करोड़ के देश मेंजबपूर्व के भारत सरकार की data.in की साइट पर स्पष्ट लिखा हुआ था कि हर दिन 10000 लोग मलेरिया से 9000 लोग टीवी से व सर्दी खांसी जन्य बीमारियों में इन्फ्लूएंजा से 4000 हजार लोग निमोनिया से 8000 लोग पूर्व से ही मरते आ रहे हैं। सन 2016 तक 25000 लोग प्रतिदिन वर्तमान में हृदयाघात से व कोरोना के टीके लगने के बाद से अचानक हृदय गति बंद होने से बच्चों से लेकर बुजुर्गो तक मृत्यु के शिकार हो रहे हैं सरकार का ध्यान उसे तरफ नहीं है कि आखिर टीका लगाने के बाद 50000 से ज्यादा लोग प्रतिदिन हृदय गति बंद होने के कारण मृत्यु को क्यों प्राप्त हो रहे हैं उसे शरीर को छुपाने भी सरकार कोरोना का तांडव कर रही है। जनता से निवेदन है कि वह डरें नहीं अपने घरों में रखे मसाले का औषधि प्रयोग कर अपने व परिवार को सुरक्षित रखें।

गूगल-माइक्रोसॉफ्ट चीन कर रहे भारतीय डाटा का दुरुपयोग

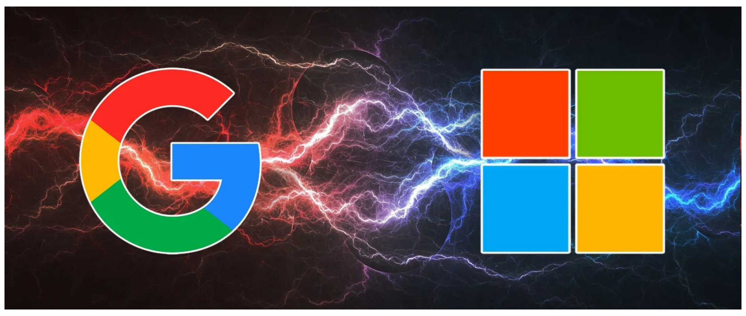

पेज 1 का शेष

दूसरी तरफ समाचार पत्रों और मीडिया द्वारा लगातार लिखे जाने के बाद में भी 10 वर्षों में भी मोदी सरकार ने अपने देश के जनता के सबसे महत्वपूर्ण आधार के डाटा को भी संचित करने रोकने गोपनीय और सुरक्षित बनाने का प्रयास न करने वह उसकी हर शासकीय विभागों में मोबाइल की सिम लेने से लेकर बच्चों से बड़े विद्यार्थियों तक के के शिक्षण संस्थानों बैंकों बीमा कंपनियों से लेकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बंटने वाले गेहूं चावल में भी आधार के डाटा का उपयोग करने के कारण आधार की ही जानकारी के कारण लाखों लोगों के बैंक खातों से लेकर हर स्थान पर उत्तर की सैंमारी में लोग आर्थिक सामाजिक रूप से ठगे जा रहे हैं सरकार के पासना तो उसको रोकने की व्यवस्था हैना जनता को सुरक्षा देने की व्यवस्था के बाद में भी आधार को पहचान के रूप मेंहर जगह अनिवार्य करन केवल जनता उनकी सरकार के सभी विभागों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर न केवल संगठित अपराधिक गिरोहों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है और भारत सरकार ने जो व्यक्तिगत अंकीय समंक संरक्षण या डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 प्रस्तुत किया। स्वाभाविक था दुनिया की जनता की मांग के साथ-साथ विभिन्न देशों में विभिन्न सरकारों ने जो गूगल फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप टिकटोक मेटा आदि के विरुद्ध जो कार्रवाइयों की उसको देखा देखी सरकार ने बिल तो अवश्य बनाया। परंतु स्वयं भारतीय जनता पार्टी और उसका आईटी सेल न केवल व्हाट्सप्प फेसबुक मैटा इंस्टाग्राम जैसी सोशल साइटों के साथ गूगल को भीमोटा पैसा देकर जनता के साथ विपक्षी और पक्ष के नेताओं की भी संदेशों ईमेल्स वीडियो बैंक खातों की लेनदेन की आदतों के डाटा की निगरानी जासूसी चोरी कर संदेशों वीडियो को बदलने, काट छांट करने अपने संदेशों वीडियो को भेजना। आदि के दुष्कर्मों को बचाने छुपाने के लिए बदनामी और कानूनी उलझन से बचने के लिए सैकड़ो खामियों कमजोर दंड के प्रावधानों के साथ, पकड़े जाने वह जनता की व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता के भंग होने पर पकड़े जाने और आरोप लगने पर और आरोप सिद्ध हो जाने पर भी बहुत छोटे आर्थिक दंड के साथ बिना जनता की वृहत स्तर पर राय जाने बिना ही थोप दिया गया है?

हाल ही में पांच राज्यों में हुए चुनाव में तीन बड़े राज्यों पर ईवीएम की जालसाजी से कब्जा करने के कारण अब वह खुलकर सबकी जासूसी करती है।

वरन् अपने ही प्रदेशों के पुराने मुख्यमंत्री मंत्रियों नेताओं के बारे में भी जनता जाने समझे नहीं उसने तत्काल ही न केवल मध्य प्रदेश वरन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी सभी शासकीय विभागों की साइटों को तत्काल बदलकर पुराने मुख्यमंत्री के सारे फोटो और विवरण हटा दिए हैं।

दूसरी तरफ अपनी जालसाजियों, भ्रष्टाचार व लूट को अंजाम देने के की बाद भी जनता की निगाहों में ना आए। जनता किसी भी प्रकार सेजनता की धन को कहां खर्च किया जा रहा है कौन-कौन उसमें संलग्न है कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं वह सारी जानकारी को सूचना अधिकार अधिनियम की धारा चार के अंतर्गत 25 बिंदुओं की जानकारी स्वमेव ही सारे विभागों को राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय से लेकर सभी शासकीय निगम मंडलों संस्थाओं विभागों से पंचायतों तक को अपने विवरण अपनी विवाह की साइट पर लोड कर देनी चाहिए थेपरंतु उल्टे ही सरकार बदलने के बाद अधिकांश के विवरण गायब कर दिए गए हैं जहां ज्यादा भ्रष्टाचार होता हैवहां की सेटिंग खोल ही नहीं है और सारी जानकारी को अत्यधिक क्लिष्ट बनाने के साथ बजट उसका उपयोग विभागीय मंत्रियों प्रधान सचिव, सचिवों, आयुक्त संचालकों प्रमुख अभियंताओं अधिकारियों इंजीनियर डॉक्टर कर्मचारियों की शिक्षा जाति के प्रमाण पत्र साथ संपति के घोषणा पत्र व के नाम पते व जिम्मेदारियां आदि का विवरण भी अधिकांश विभागीय साइटों से गायब है। जो सरकारी जिम्मेदार कर्मचारियों अधिकारियों की न केवल जालसाजियों के साथ भ्रष्ट मानसिकता को भी प्रकट करता है।

केंद्र सरकार के आईटी विभाग को चाहिए की सबसे पहले वह 140 करोड़ जनता के आधार के साथ अन्य प्रकार के डाटा के साथ सभी शासकीय विभागों संस्थानों के डाटा को सुरक्षित करने के लिए अपना शासकीय डिजिटल डाटा बैंक तैयार करें और सभी विभागों को केंद्र से लेकर राज्यों तक के गूगल के जीमेल गूगल मीट कॉन्फ्रेंस, गूगल सीट गूगल फॉर्म्स आदि सेवाओं के विकल्पअपने देश में तत्काल तैयार करने के साथ गूगल की सभी सेवाओं का सभी प्रकार से हर स्तर पर उपयोग करना बंद कर दे। दुनिया के अनेकों देश में इसी डाटा के दुरुपयोग के कारण गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वह अन्य प्रकार के ऐप से व जुड़ी जनता के व्यक्तिगत डाटा के दुरुपयोग पर हजारों करोड रुपए का दंड थोपने के साथ डाटा की निगरानी, विश्लेषण व्यवसायिक कमाई बेचने आदि परवी उसके कुल आय का 2 से 5% तक का दंड ठोकने की व्यवस्था करनी चाहिए।

Google का $400 मिलियन जुर्माना और 2023 विज्ञापन योजनाओं पर 5 सबसे बड़े डेटा गोपनीयता जुर्माने का प्रभाव

उपयोगकर्ताओं के स्थानों को अवैध रूप से ट्रैक करने के लिए इस सप्ताह उददुत के खिलाफ लगाए गए ऐतिहासिक जुर्माने के बाद, हमने अब तक के सबसे बड़े डेटा गोपनीयता और सुरक्षा नियामक जुर्माने को सूचीबद्ध किया है - और उद्योग हितधारकों के लिए इसका क्या अर्थ है, इसका खुलासा किया है। यह कहानी द ड्रम के सप्ताह भर चलने वाले डेटा और प्राइवेसी डीप डाइव का हिस्सा है।

इंस्टाग्राम - $403m (2022)

जीडीपीआर में उल्लिखित बच्चों की गोपनीयता सुरक्षा का उल्लंघन करने के लिए आयरलैंड के डेटा संरक्षण आयुक्त ने सितंबर में इंस्टाग्राम पर 403 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया था। शिकायत एक लंबे समय से चले आ रहे प्लेटफ़ॉर्म मुद्दे पर केंद्रित थी, जिसने युवा उपयोगकर्ताओं के फ़ोन नंबर और ईमेल पते सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए थे, जब वे व्यवसाय या निर्माता खातों में अपग्रेड हुए थे (संभवतः प्रोफ़ाइल दृश्य और पोस्ट सहभागिता जैसी खाता विश्लेषण सुविधाओं को देखने के लिए)। यह निर्णय 2020 में शुरू की गई एक जांच के बाद आया, जिसका लक्ष्य यह आकलन करना था कि सोशल प्लेटफ़ॉर्म 13 से 17 वर्ष की आयु के उपयोगकर्ताओं के डेटा को कैसे संभालता है। इंस्टाग्राम ने पूरी जांच के दौरान आयरिश नियामक संस्था के साथ सहयोग किया।

गूगल - $391.5 मिलियन (2022)

इसी सप्ताह, उददुत 40 अमेरिकी राज्यों के आरोपों पर 391.5 मिलियन डॉलर के समझौते पर सहमत हुआ है कि तकनीकी दिग्गज ने अवैध रूप से उपयोगकर्ताओं के स्थानों को ट्रैक किया है। जुर्माना भरने के अलावा, उददुत को उपयोगकर्ताओं के स्थान को ट्रैक करने और एक समर्पित वेब पेज पर स्थान-ट्रैकिंग डेटा के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करने के मामले में अधिक स्पष्ट और पारदर्शी होने की भी आवश्यकता है। यह निर्णय 2018 में राज्य के वकीलों के नेतृत्व में एक जांच शुरू होने के बाद आया। आयोवा अटॉर्नी जनरल टॉम मिलर ने सोमवार को एक बयान में कहा, 'जब उपभोक्ता अपने उपकरणों पर स्थान डेटा साझा नहीं करने का निर्णय लेते हैं, तो उन्हें भरोसा करना चाहिए कि कंपनी अब उनकी हर गतिविधि पर नज़र नहीं रखेगी।' 'यह समझौता यह स्पष्ट करता है कि कंपनियों को ग्राहकों को ट्रैक करने के तरीके में पारदर्शी होना चाहिए और राज्य और संघीय गोपनीयता कानूनों का पालन करना चाहिए।'

अमेज़न - $877 मिलियन (2021)

जुलाई 2021 में, लक्ज़मबर्ग में यूरोपीय नियामकों ने डेटा उल्लंघनों और जीडीपीआर के तहत सामान्य डेटा प्रोसेसिंग सिद्धांतों का पालन करने में विफल रहने के लिए अमेज़न यूरोप पर 877 मिलियन डॉलर का भारी जुर्माना लगाया। अधिकारियों ने अमेज़ॅन को अनिर्दिष्ट 'अभ्यास संशोधन' का भी काम सौंपा। जुर्माना विशेष रूप से भारी है - यह अपनी क्षमता का पहला जीडीपीआर जुर्माना था, और यह ऐसे समय में आया जब कई गोपनीयता समर्थक ढीले और अप्रभावी प्रवर्तन से थक गए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि संख्या के कारण कई गुना हो सकते हैं। गोपनीयता और अनुपालन फर्म वनट्रस्ट के मुख्य ट्रस्ट अधिकारी एंड्रयू क्लियरवॉटर कहते हैं, 'प्रत्येक प्रमुख गोपनीयता कानून में जुर्माना निर्धारित करने की एक अलग पद्धति है, लेकिन अंतर्निहित विषय यह है कि उल्लंघन जितना अधिक 'गंभीर' होगा, जुर्माना उतना ही बुरा होगा।'

भारतीय प्रताड़ना सेवा के पीएस घोर धूर्त भ्रष्टों के बदलें विभाग

पेज 8 का शेष

प्रदेश की अधिकांश संभागों में प्रमोटी भारतीय प्रताडना सेवा अधिकारी जो कि घोर जालसाज, भ्रष्ट होने के साथ भू-कॉलोनी माफियाओं के संरक्षणदाता होने के कारण मोटा धन खर्च कर पदोन्नति से प्रशासनिक सेवा का पद खरीदे गए अधिकारी बैठे हुए हैं। उनके पास एक नहीं दो-दो संभागों का प्रभार है।

सुशासन और प्रभावी शासन के लिए अनुभवी और सीनियर अधिकारियों को ही कमिश्नर बनाया जाता लेकिन है, शिवराज सरकार में चुनावी साल के दौरान आईएएस अफसर की पोस्टिंग मनमाने तरीके से की गई। ऐसे अधिकारियों को बैठाया जो पहले भी और बाद में भी परफॉर्म नहीं कर पाए थे। चूंकि संभाग के अधीन कई जिले होते हैं इसलिए संभाग आयुक्त का पद बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील हो जाता है।

इस पद पर कुशल अधिकारी की नियुक्ति जरूरी होती है। पिछली सरकार में यह सब पैमाने धरे के धरे रह गए और पिक एंड चूस की थ्योरी पर जो अधिकारी भारी पड़ा उसे कमिश्नरी सौंप दी गई। आधे प्रदेश में इस समय एक कमिश्नर दो दो संभाग संभाले बैठा है और वह कमिश्नर भी प्रमोटी आईएएस (एडिशनल सेक्रेटरी) के तौर पर पोस्टिंग पाए हुए हैं। यह देखकर ऐसा लगता है कि प्रदेश में आईएएस अफसरों का भारी टोटा है, जबकि असल में कई सारे योग्य आईएएस अधिकारी लूप लाइन में डाल रखे हैं। ड्रीम पोस्टिंग वाले संभाग इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा आदि संभागों में पंसदीदा अधिकारियों को कमिश्नर बनाया गया।

प्रदेश में जितने भी संभाग हैं उनमें से आधे संभागों में प्रमोटी आईएएस पदस्थ हैं। इनमें जूनियर सेक्रेटरी तक पहुंचे अधिकारी राज कर रहे हैं। मुख्य पदों पर पोस्टिंग योग्यता का पैमाना नहीं होकर राजनीतिक आकाओं की पसंद से तय होता है।

इंदौर जैसी पोस्टिंग पवन शर्मा को मिली थी। वह करीब 3 साल

पहले इंदौर कमिश्नर के पद पर आए थे। उनके बारे में भी बताया जाता है कि उन्हें संघ और संगठन का बेकिंग रहा है।

उनके बंगले पर भाई साहब लोगों का आना-जाना और भोजन कार्यक्रम की चर्चा में रहते थे। इसके बाद उन्हें भोपाल कमिश्नर जैसी महत्वपूर्ण पोस्टिंग दी गई और साथ में उन्हें नर्मदापुरम संभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया गया। इंदौर में मालसिंह को कमिश्नर बनाया गया जो पहले भोपाल में कमिश्नर थे। इनकी पोस्टिंग के पीछे भी बताते हैं कि इन्हें संघ का भी समर्थन था।

इसी तरह से ग्वालियर संभाग के कमिश्नर चंबल संभाग के भी राजा बने हुए हैं। चंबल संभाग पिछड़ा, गरीब, अशिक्षा आदि समस्याओं से ग्रस्त है। यहां पर पूर्णकालिक कमिश्नर की जरूरत थी, लेकिन यह सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। चंबल जैसे संभाग की सल्तनत की कमान ग्वालियर में बैठे कमिश्नर के हाथों में पकड़ा दी गई। ग्वालियर के संभाग आयुक्त पद पर दीपक सिंह विराजमान हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि धार्मिक, राजनीतिक और ब्यूरोक्रेसी में संपर्कों के आधार पर वे मुख्य धारा में बने रहे। आईएएस बनने से पहले और बाद तक ड्रीम पोस्टिंग पाते रहे।

आईएएस अवार्ड होते ही वे लंबे समय तक कलेक्टर की पोस्टिंग पाते रहे। इसी तरह से भोपाल कमिश्नर पवन शर्मा के पास भी बेहद महत्वपूर्ण नर्मदापुरम संभाग का अतिरिक्त प्रभार है, जबकि उनके समकक्ष और उनसे कतई कमतर नहीं ऐसे आईएएस अधिकारियों को सरकार ने घर बैठाए हुए रखा है। सरकार के इस तरह के अंधेरे गर्दी वाले शासन- प्रशासन की ब्योरोक्रेसी में भी काफी आलोचना की जाती है।

कुशासन का मामला यहीं तक सीमित नहीं है। जबलपुर संभाग में भी अतिरिक्त सचिव अभय वर्मा को कमिश्नर बनाया था, जबकि उनसे प्रधान सचिव रैंक के कई अधिकारी मौजूद थे। वर्मा को चुनाव के पहले कमिश्नर बनाया गया था।

शहडोल संभाग में इसी तरह से प्रमोटी राजीव शर्मा को कमिश्नर बनाया था, लेकिन उन्होंने सरकार के चाल चरित्र को देखते समझते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना ही उचित समझा। शर्मा के स्थान पर नए संभाग आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गई। इसका अतिरिक्त प्रभार रीवा कमिश्नर अनिल सुचारी को दे दिया।

कहा जा रहा है कि नई सरकार में भी ऐसे ही अधिकारी राज करेंगे, योग्य अधिकारियों को शायद ही मौका मिलेगा, क्योंकि जो अधिकारी जमे हुए हैं वे हर तरह से पसंदीदा पोस्टिंग पाने के लिए शक्ति केंद्रों के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जो पिछली सरकार में भी ताकतवर थे और इस समय भी दमदार शक्ति केंद्र बने हुए हैं।

जायफल

इनफर्टिलिटी की समस्या दूर करे

मोटापा घटाकर स्लिम-फिट बनाए जोड़ों के दर्द से राहत दिलाए; दूध संग पीने से छूमंतर होगी टेंशन

- जायफल सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के साथ-साथ लूज मोशन में आराम मिलता है। एलर्जी से बचाव करने में भी मदद कर सकता है।
- आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर आर पी पराशर का कहना है कि अगर लौंग, शहद, दूध और मिश्री को जायफल के साथ अलग-अलग लिया जाए तो इसके चमत्कारी फायदे कई बीमारियों से राहत दिला सकते हैं।
- साथ ही इम्यूनिटी बूस्ट भी करते हैं। लेकिन गर्मियों में इसका सेवन कम मात्रा में ही करें। इसकी तासीर गर्म होती है, जो गर्मियों में समस्या को बढ़ा सकती है।

सबसे पहले बात करते हैं जायफल और लौंग के फायदे और नुकसान के बारे में।

गुणों का जखीरा जायफल

गर्मियों में भी कई लोगों को सर्दी-खांसी और जुकाम की समस्या होती है। इसे दूर करने के लिए जायफल और लौंग से तैयार चाय पी सकते हैं। यह खांसी, जुकाम जैसी परेशानी को दूर करने में प्रभावी होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो फ्लू से बचाता है।

इनफर्टिलिटी की समस्याओं में करे सुधार

प्राचीन काल से ही लौंग और जायफल जैसे मसालों का इस्तेमाल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है। इनफर्टिलिटी की समस्या खत्म करने के लिए जायफल और लौंग का काढ़ा पीना फायदेमंद हो सकता है।

वजन घटाने में असरदार

लौंग और जायफल में मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने का गुण होता है। रोजाना लौंग और जायफल की चाय पीने से कैलोरी काफी तेजी से बर्न होती है और मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है।

इम्यूनिटी बूस्टर है जायफल

लौंग और जायफल एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल गुणों से भरपूर है। इसमें मौजूद सभी गुण इम्यूनिटी बूस्ट करने में असरदार है।

गले में खराश करे कम

गले की समस्याओं से राहत पाने के लिए लौंग और जायफल की चाय का सेवन करना चाहिए। गले में मौजूद कफ और सूजन कम हो सकती है।

स्किन के लिए बेमिसाल

लौंग और जायफल के पाउडर को मिक्स करके चेहरे पर लगाने से एक्ने, पिंपल्स की परेशानी दूर होती है। इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पिंपल्स में होने वाली सूजन को कम करता है।

आइए अब जानते है जायफल और मिश्री के गुणों के बारे में।

जायफल और मिश्री भी सेहत से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में फायदेमंद है। कई आयुर्वेदिक औषधि में इसका इस्तेमाल करते हैं।

यूरिन इन्फेक्शन होगा दूर

जायफल और दूध का एक साथ सेवन करने से यूरिन इन्फेक्शन की परेशानी दूर हो सकती है। जायफल को घिस लें। अब इसमें 1 चम्मच मिश्री लें। अब इन दोनों को दूध में मिलाकर पिएं। इससे यूटीआई की परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है।

आर्थराइटिस के दर्द से राहत

जायफल में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, जो गठिया के दर्द को दूर करने में असरदार है। यह मांसपेशियों के दर्द से भी छुटकारा दिलाता है। रोजाना दूध के साथ मिश्री और जायफल लेने से आर्थराइटिस में होने वाले दर्द से छुटकारा मिल सकता है।

अनिद्रा से छुटकारा

मिश्री और जायफल का सेवन करने से अनिद्रा की परेशानी दूर हो सकती है। यह दिमाग को शांत करके नींद लाने में असरदार है।

रोजाना रात में सोने से पहले गुनगुने दूध के साथ जायफल का पाउडर और मिश्री को मिक्स करके लें। इससे काफी गहरी और अच्छी नींद आएगी।

मुंह से बदबू भगाए

मिश्री और जायफल का मिश्रण मुंह की बदबू से छुटकारा दिलाने में कारगर है। इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण सांसों में आने वाली बदबू को कम कर सकता है। साथ ही कैविटी से छुटकारा दिला सकता है। रोजाना रात में मिश्री और जायफल को गुनगुने दूध के साथ लें।

आइए न्यूट्रिशन से भरपूर शहद और जायफल की खूबी के बारे में जानते हैं।

शहद और जायफल का सेवन एक साथ किया जाए तो सेहत को कई फायदे हो सकते हैं। शहद के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी, विटामिन बी6, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। वहीं जायफल में भी प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटैशियम, सोडियम, जिंक, विटामिन सी, विटामिन बी 6, विटामिन ए पाया जाता है।

पेट की समस्या हो दूर

पेट की समस्या को दूर करने में शहद और जायफल बेहद असरदार है। जायफल के चूर्ण को या उसके तेल को शहद के साथ मिलाकर चटनी बनाकर इस्तेमाल करें। ऐसा करने से डाइजेशन बेहतर होगा और पेट की सभी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। इसका सेवन सोने से पहले या सुबह खाली पेट कर सकते हैं।

जायफल का कई और समस्याओं में भी इस्तेमाल होता है। जायफल और सरसों के तेल का मिश्रण पुरानी चिकित्सा पद्धति है। बच्चों को सर्दी-खांसी होने पर जायफल और सरसों तेल का मिश्रण दिया जाता है।

जोड़ों के दर्द में राहत

जोड़ों में दर्द की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो सरसों के तेल में 2 जायफल को डालकर रात भर के लिए भिगोकर छोड़ दें। सुबह इस तेल से जोड़ों की मालिश करें। रोजाना मालिश करने से आराम मिलेगा।

मांसपेशियों के दर्द से राहत

जायफल और सरसों का तेल जोड़ों में दर्द के साथ-साथ मांसपेशियों के दर्द से भी राहत मिलती है। सरसों तेल में जायफल का पाउडर डालकर मालिश करने से मांसपेशियों की सूजन को कम किया जा सकता है।

कैंसर से बचाव करे

जायफल का इस्तेमाल कैंसर से बचाव में कुछ हद तक मददगार हो सकता है। इस विषय से जुड़े एक अध्ययन में पाया गया है कि जायफल में एंटीट्यूमर गुण पाए जाते हैं, जो कैंसर का कारण बनने वाले ट्यूमर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। जायफल के तेल का इस्तेमाल से कैंसर से बचने के लिए किया जाता है।

घाव के निशान को कम करे

जायफल और सरसों का तेल घाव के निशान को कम करने में असरदार है। एक चम्मच जायफल पाउडर में एक चम्मच सरसों का तेल मिलाकर घाव पर लगाने से निशान दूर होगा। जायफल पाउडर के बजाय जायफल के तेल को भी सरसों तेल में मिला सकते हैं।

फटी एड़ियों से राहत

जायफल और सरसों के तेल का इस्तेमाल करने से फटी एड़ियों की परेशानी दूर हो सकती है। इसका इस्तेमाल करने के लिए जायफल पाउडर को सरसों तेल में मिक्स कर लें। अब इस तेल को एड़ियों पर लगाएं। रोजाना इस्तेमाल करने से परेशानी दूर हो सकती है।

जायफल का तेल किडनी, लिवर की सफाई करे:

भूख बढ़ाए, दिमाग तेज करे, सांसों की बदबू से निजात दिलाए; ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह

जायफल का इस्तेमाल खाना बनाने के साथ-साथ कई बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है। लेकिन जायफल का तेल भी सेहत के लिए रामबाण है। जायफल के तेल का इस्तेमाल ऑप्शनल है। सेहत से जुड़ी परेशानियों से बचने और इसके लक्षण को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जान-जहान के इस आर्टिकल में आयुर्वेदाचार्य डॉ. आर.पी पराशर से जानते हैं जायफल के तेल के फायदे और नुकसान के बारे में।

सबसे पहले जायफल तेल के फायदे के बारे में जान लेते हैं।

भूख बढ़ाए

जायफल के तेल में मौजूद फेनिलप्रोपेनाइड यौगिक की वजह से यह तेल भूख बढ़ाने में मदद करता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए जायफल के तेल की कुछ बूंदों को डिफ्यूजर में डालकर कमरे में रख दें और इसे इन्हेल करें।

सांसों की दुर्गंध से निजात दिलाए

जायफल सांसों की बदबू को दूर करने में मददगार हो सकता है। जायफल का तेल एंटीमाइक्रोबियल गुण से भरपूर होता है, जो मुंह में बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद कर सकता है। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल कई टूथपेस्ट में भी किया जाता है। जायफल तेल में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक गुण पाए जाते हैं, जो मसूड़ों में होने वाली सूजन को और दांतों में होने वाले दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए जायफल तेल की कुछ बूंदों को पानी में डालकर कुल्ला किया जा सकता है।

दिमाग तेज करे, याददाश्त मजबूत करे

जायफल का तेल दिमाग की सेहत के लिए फायदेमंद होता है। यह दिमाग को तेज करता है और याददाश्त बढ़ाता है। यह मिर्गी के दौरों से बचाता है। लेकिन ध्यान रहे इसका इस्तेमाल कम मात्रा में ही करें।

दर्द की दवा है जायफल का तेल

जायफल के तेल में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। इस तेल को प्रभावित हिस्से में लगाने पर दर्द और सूजन से छुटकारा मिलता है। पेट में दर्द हो तो हल्के हाथों से तेल से मालिश करें।

जायफल को डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं। कॉफी , चाय, गर्म दूध या गर्म चाकलेट के साथ।

यौन शक्ति बढ़ाने में कारगर

जायफल का अर्क, तेल या रस या चूर्ण यौन शक्ति बढ़ाने में मददगार है। जायफल के एथेनॉल अर्क के इस्तेमाल करने पर कामेच्छा और शक्ति दोनों बढ़ती है। लेकिन जायफल तेल का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

किडनी और लिवर से निकाले 'जहर'

डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जायफल का तेल काफी असरदार है। किडनी और लिवर की सफाई के लिए जायफल का तेल बेहतरीन लिवर टॉनिक की तरह काम करता है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालकर लिवर को होने वाले नुकसान को रोकने के साथ ही गुर्दे की पथरी होने से बचाता है। जायफल के तेल में मौजूद मिरिस्टिसिन यौगिक लिवर को हेल्दी बनाने का काम करता है।

मसल्स और जोड़ों के खिंचाव से राहत दिलाए

जायफल के तेल का एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मसल्स में होने वाले खिंचाव और दर्द को कम करता है। साथ ही यह जोड़ों की सूजन से भी राहत दिलाने का काम कर सकता है।

मुंहासे दूर करे, झुर्रियां पास न आएं

जायफल के तेल में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं। ये कील-मुंहासों को कम करने में मदद करते हैं, क्योंकि पिंपल बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। साथ ही यह एंटी-इंफ्लेमेटरी की तरह भी काम करता है, जो मुंहासों से प्रभावित हिस्से में होने वाली सूजन को कम करने में मददगार है। रूई में एक बूंद जायफल का तेल डालकर मुंहासे वाली जगह पर लगाएं। इससे मुंहासे और इसके दाग दूर हो जाएंगे। ये झुर्रियों से बचाने में मदद करता है।

जायफल तेल का ऐसे करें इस्तेमाल

जायफल के इस्तेमाल से तो अब तक वाकिफ हो चुके होंगे, लेकिन जायफल के तेल का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, इसके लेकर लोगों में उलझन बनी रहती है।

-जायफल के तेल का इस्तेमाल अरोमा थेरेपी के लिए भी होता है।

-जायफल के तेल का इस्तेमाल फ्लेवर के लिए मिठाई या बेकरी प्रोडक्ट्स में भी होता है।

-जायफल का तेल डिफ्यूजर में डालकर इन्हेल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

-जायफल का तेल सीधे मसूड़ों पर लगाएं। जायफल के तेल से मसाज कर सकते हैं। जायफल तेल की कुछ बूंदों को पानी में डालकर माउथवॉश कर सकते हैं।

जायफल का तेल बनाने का तरीका

जायफल का तेल बाजार में आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसे घर में भी बनाया जा सकता है। जायफल का तेल बनाने के लिए जायफल को दरदरा पीसकर इसे एयर टाइट कांच के जार में डाल लें। पिसे हुए जायफल में नारियल या कोई भी तेल मिला लें। इसमें मौजूद तेल को अच्छे से मिलाएं और इसे धूप में कम से कम 48 घंटों के लिए रखें। धूप में रखने के बाद इसे समय-समय पर हिलाते भी रहें। 48 घंटे के बाद इसे छानकर दूसरी बोतल में डाल लें। इस प्रक्रिया को दो बार दोहराएं। यानी तेल छानने के बाद एक बार फिर उसमें आधा कप पिसा हुआ जायफल डालकर धूप में सुखाकर छान लें। घर में बना शुद्ध जायफल का तेल तैयार है।

जायफल का तेल बनाने के तरीके के बाद बात करते हैं, इस तेल से होने वाले नुकसान के बारे में।

जायफल तेल से नुकसान

जायफल तेल के फायदे के साथ ही कई नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल कम मात्रा में ही करना चाहिए। इसका ज्यादा इस्तेमाल नुकसान पहुंचा सकता है।

डिस्क्लेमर-जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से जायफल तेल के नुकसान भी हो सकते हैं। इस आर्टिकल में मौजूद जानकारी सिर्फ एक सलाह के तौर पर दी गई है। अगर किसी भी तरह की बीमारी या एलर्जी के शिकार हैं तो इस्तेमाल करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें।

जायफल वाला दूध पीना बेहद फायदेमंद है। जायफल से नींद की क्वालिटी बेहतर बनाई जा सकती है।

दूध में जायफल मिलाकर पीने से भी सेहत को मिलते हैं फायदे। जानें किस समय पीना है ज्यादा फायदेमंद

शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है या शरीर में प्रोटीन का स्तर बढ़ाना होता है तो दूध या दूध से बनी चीजों को डाइट में शामिल करने की सलाह दी जाती है। दूध और जायफल का एक साथ लेने से कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। एक गिलास दूध में जायफल पाउडर मिलाकर पीना फायदेमंद है। रात में सोने से पहले या शाम के वक्त इसके सेवन से काफी फायदा मिल सकता है।

तनाव को दूर करे

मानसिक समस्याओं को दूर करने में जायफल और दूध बेहद फायदेमंद है। जायफल में एंटी स्ट्रेस गुण होते हैं जो तनाव को दूर करके मूड को फ्रेश रख सकता है।

जायफल की ज्यादा मात्रा नुकसान पहुंचा सकती है

- ड्राई माउथ की समस्या भी हो सकती है।
- गर्मियों में ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदायक है।
- गैस्ट्रिक की समस्या से जूझ रहे मरीज दूर रहें।
- घबराहट, उल्टी और मतली जैसी परेशानियां हो सकती हैं।
- इसकी अधिक मात्रा नशीले पदार्थ की तरह असर करती है।
- जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से दिल की धड़कनें तेज हो सकती है।

डिस्क्लेमर- अपनी डाइट में जायफल को जोड़ने से पहले एक बार एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

पेट दर्द में जायफल है रामबाण

नींबू, अदरक, गुड़, छाछ के साथ लें, दूर होगी एसिडिटी, लूज मोशन, पेट दर्द की समस्या

पेट दर्द, गैस, कब्ज जैसी पेट की समस्याएं दूर करने का आसान उपाय है जायफल का सेवन, लेकिन इसके लिए इस्तेमाल का सही तरीका और सही मात्रा में सेवन की जानकारी होना जरूरी है। जायफल के इस्तेमाल और फायदे-नुकसान के बारे में बता रहे हैं आयुर्वेदाचार्य डॉ. सिद्धार्थ सिंह।

पेट दर्द में क्यों फायदेमंद है जायफल

अपच की वजह से पेट में दर्द हो सकता है। जायफल का सेवन करने से अपच की समस्या दूर होती है। डाइजेशन सिस्टम बेहतर रहता है। डॉ सिद्धार्थ कहते हैं कि आयुर्वेद में पेट से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए जायफल रामबाण माना गया है।

जायफल-नींबू

नींबू पेट में एसिड की परेशानी को दूर करता है। जायफल के साथ नींबू के सेवन से सिर दर्द, माइग्रेन का दर्द और दांत दर्द दूर होता है।

जायफल-सोंठ

जायफल पाउडर में सोंठ मिला लें। 2 चम्मच जायफल पाउडर ले रहे हैं, तो उसमें 1 चम्मच नींबू का रस मि?लाएं। इससे पेट में दर्द की समस्या दूर होगी। इस मिश्रण को आप गुनगुने पानी में मिलाकर पी सकते हैं।

जायफल-शहद

जायफल और शहद पेट दर्द दूर करते हैं। जायफल के चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर खाने से गैस और दस्त की समस्या से छुटकारा मिलता है। इसमें थोड़ा घी मिलाकर भी ले सकते हैं।

जायफल-अदरक-दालचीनी-सेंधा नमक

जायफल के साथ अदरक, दालचीनी, सेंधा नमक मिलाएं। इसका सेवन करने से दस्त, पेट में दर्द की समस्या दूर होती है। इस मिश्रण का सेवन गुनगुने पानी के साथ कर सकते हैं।

जायफल-गुड़

गैस्ट्रिक समस्याओं को दूर करने के लिए रोजाना जायफल और गुड़ खा सकते हैं। जायफल, नींबू और गुड़ को मिलाकर चाय बनाकर भी पी सकते हैं।

जायफल-छाछ

पेट दर्द दूर करने के लिए जायफल के पाउडर में छाछ में मिलाएं। छाछ पेट के लिए फायदेमंद है। अपच या गैस की समस्या हो रही है, तो जायफल के साथ छाछ का सेवन फायदेमंद है।

एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से युक्त जायफल पेट, मसल्स के दर्द और सूजन से छुटकारा दिलाता है

बच्चों के लिए जायफल के फायदे

छोटे बच्चे अक्सर पेट दर्द या मौसमी बीमारियों से परेशान रहते हैं। ऐसे में जायफल की सही मात्रा देकर उन्हें इन समस्याओं से दूर रखा जा सकता है। आइए, जानते हैं कि बच्चों को जायफल कैसे और कितनी मात्रा में दें।

पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स को रखे दूर

अक्सर बच्चों के पेट में गैस बनने लगती है, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसे में जायफल के सेवन से उन्हें इस समस्या से छुटकारा दिलाया जा सकता है। बच्चों को जायफल देने से पेट में ऐंठन या दर्द से तुरंत आराम मिलता है।

अच्छी नींद के लिए

बच्चों की दूध की बोतल में थोड़ा सा जायफल पाउडर मिला देने से वो शांत हो कर सो जाते हैं। इससे उनके पेट में कोई तकलीफ नहीं होती, जिससे उनकी नींद बीच में टूटती नहीं है।

डाइजेशन की समस्या से छुटकारा

छोटे बच्चों का पाचन तंत्र ठीक से डेवलप न होने के कारण उन्हें अपच की समस्या हो सकती है। ऐसे में ठोस आहार देने से उनके पेट में दर्द, गैस या दस्त भी हो सकता है। दस्त के समय शिशु को जायफल देना कारगर साबित हो सकता है।

सर्दी-खांसी के इलाज में मददगार

जायफल की तासीर गर्म होती है जिससे सर्दी-खांसी कुछ समय में ठीक हो जाती है। ठंड से बचाने के लिए बच्चों को जायफल देना सबसे प्रभावी घरेलू उपचारों में से एक है।

जायफल देने का तरीका

बच्चे की डाइट में जायफल जरूर शामिल करें। जायफल को 1 चम्मच दूध या पानी के साथ पत्थर पर घिसकर पीस लें। इस पेस्ट को बच्चे के दूध, दलिया, अनाज मिलाकर उसे दें।

कितना डोज देना होगा सही

जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता, तब तक उसे जायफल नहीं देना चाहिए। छह महीने के बाद गर्मियों के मौसम में इसे दिन में एक बार 0.5 मिलीग्राम और सर्दियों में 0.5 मिलीग्राम दो बार दे सकते हैं। बच्चे को जायफल का सेवन कराने से पहले चाइल्ड स्पेशलिस्ट से सलाह लें।

फर्टिलिटी बढ़ाए जायफल

आज की महिलाओं पर करियर बनाने का स्ट्रेस ज्यादा है। इस चक्कर में वो देर से शादी करती हैं और फिर बच्चे के लिए भी उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ फर्टिलिटी पावर कम होने लगता है। कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, तो कुछ घरेलू नुस्खों की मदद से फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सकता है।

जायफल-मिश्री

तीन जायफल और तीन चम्मच मिश्री को पीस कर पाउडर बना लें। आधा-आधा चम्?मच दोनों पाउडर डालकर मिक्स करें। पीरियड्स खत्म होने के पांचवें दिन से रोजाना एक चम्मच पाउडर को पानी के साथ लेना है। एक दिन भी स्किप नहीं करना है। पहली बार जिस समय इसका सेवन कर रही हैं, रोज उसी समय पर इसे खाएं। इसके सेवन के साथ-साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि प्रेग्नेंट होने के लिए सही समय पर कोशिश करना भी जरूरी है। पीरियड्स खत्म होने के 11वें दिन से 18वें दिन तक रोज ट्राई करने पर प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।

आयुर्वेद के अनुसार, जायफल नर्वस सिस्टम को शांत करता है और महिलाओं के प्रजनन अंगों में खून के प्रवाह को बढ़ाता है। यही वजह है कि प्रेग्नेंट होने के लिए जायफल का सेवन करने की सलाह दी जाती है।

हार्मोन बैलेंस करे

रोज जायफल खाने से शरीर में हार्मोनल बैलेंस ठीक करने में मदद मिलती है। इससे पीरियड्स, मेनोपॉज, डिप्रेशन, एंग्जायटी जैसी बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है।

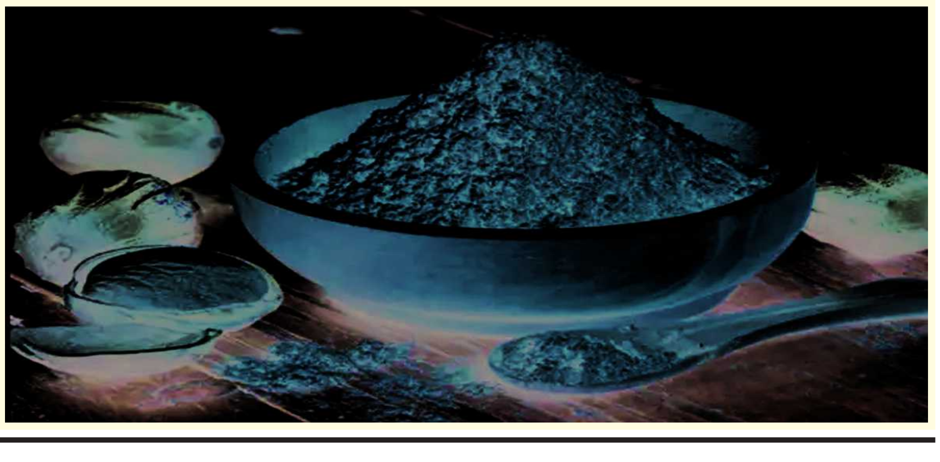

आदिम जाति विभाग में जिलाधीशों और आयुक्तों के आदेशों की उड़ाते हैं धज्जियां

प्रदेश के आदिम जाति विभाग में मचा जालसाजियों और भ्रष्टाचार का तांडव

21 आदिम जाति जिलों में चल रहा है भ्रष्टाचार से लूट व बंदरबांट

प्रदेश के 10 संभागों के 21 जिले आदिवासी जिलों की श्रेणी में है। भोपाल उज्जैन ग्वालियर सागर संभागों को छोड़कर 6 संभागों में 21 जिलों मैं केंद्र व राज्य शासन का 20 ज्यादा योजनाओं में हजारों करोड़ खर्च होने उपरांत भी 75 साल की आजादी के बाद भी लक्षित विकास नहीं दिखता। इसके मूल कारणों में चारों तरफ हर कदम मुख्यमंत्री मंत्री प्रधान सचिव से लेकर संभाग आयुक्तों जिलों के कलेक्टरों से लेकर आयुक्त आदिम जाति विकास उपायुक्तों, और आदिम जाति जिलों के सहायक आयुक्त जल साथियों भ्रष्टाचार से लगभग 40 से 50% पैसा हजम कर बंदरबांट करते हैं। इसलिए आदिम जाति जिलों के विकास खंडों से गांवों तक सभी योजनाओं के विकास के साथ गांव में फैले प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों छात्रावासों में खर्च होने वाला और विद्यार्थियों को बंटने वाली देसी विदेशी अध्ययन के लिए छात्रवृतियों पुरस्कार ऑन आदि में भारी जालसाजी की जाती हैं।

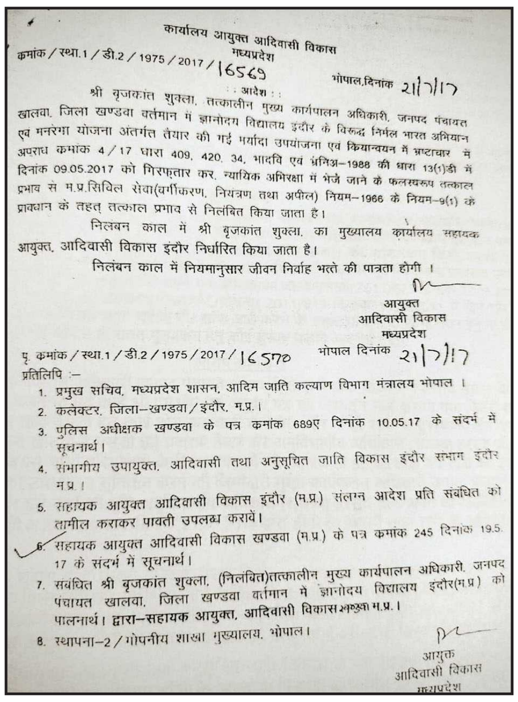

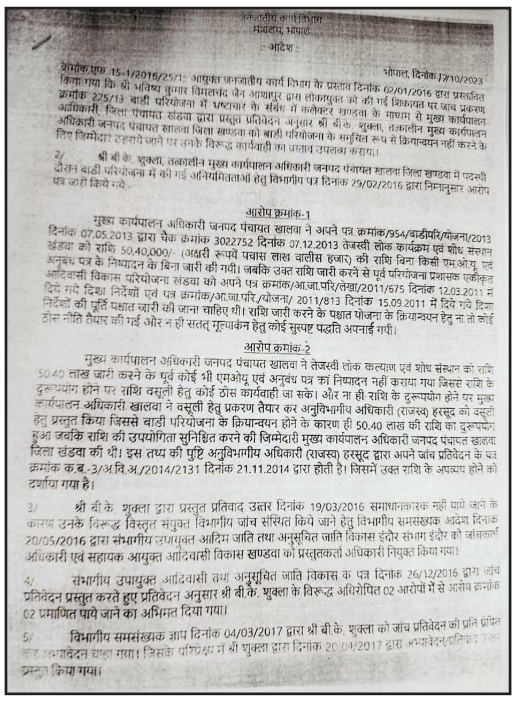

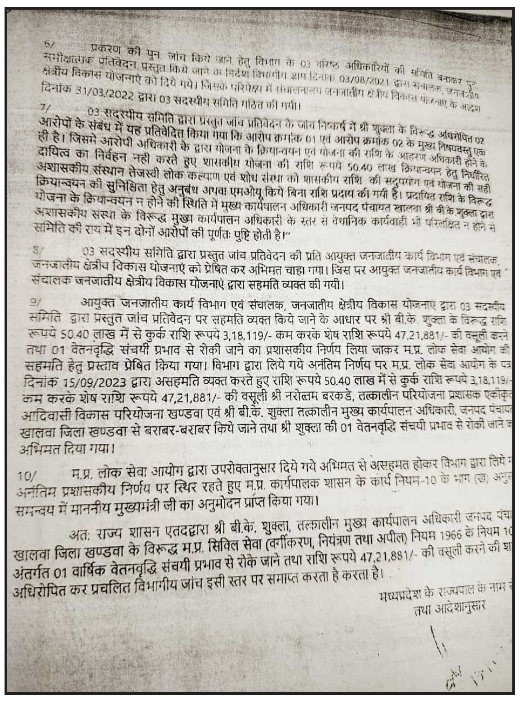

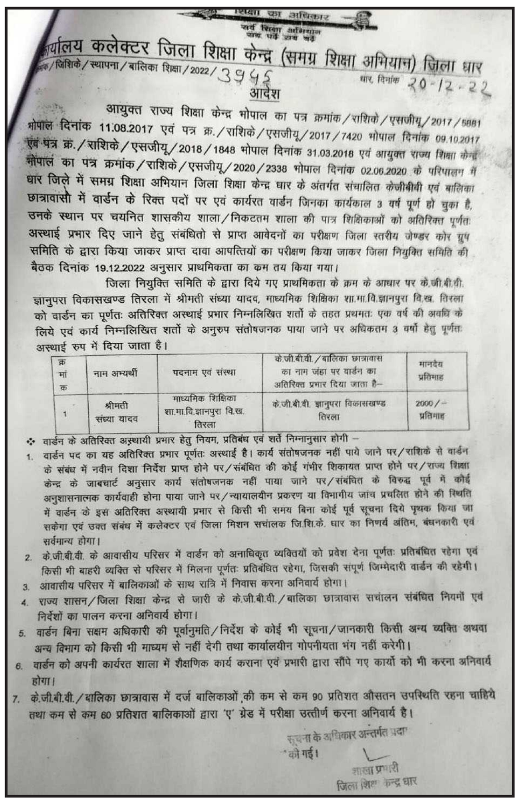

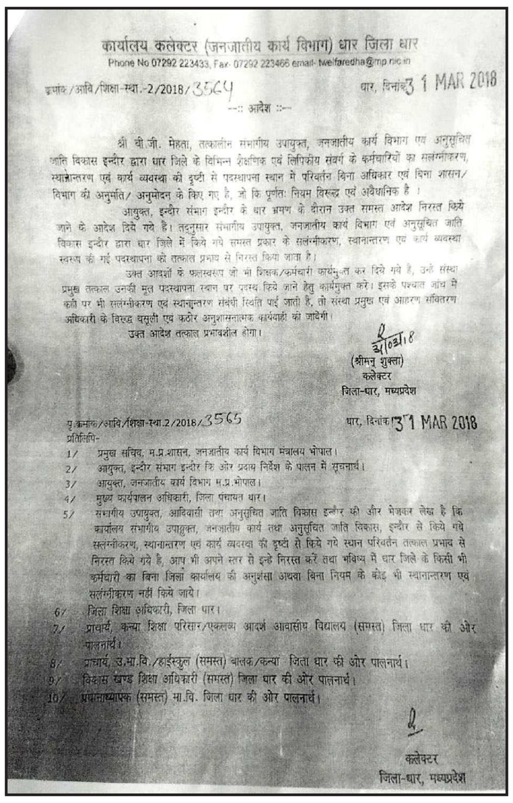

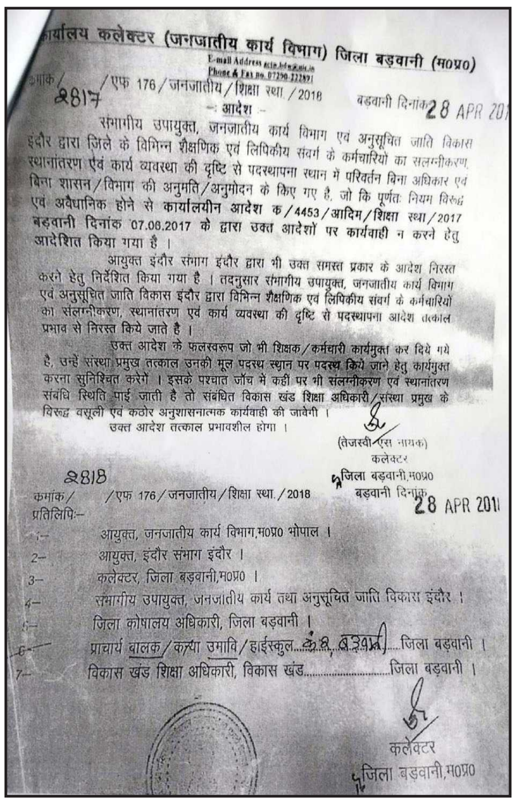

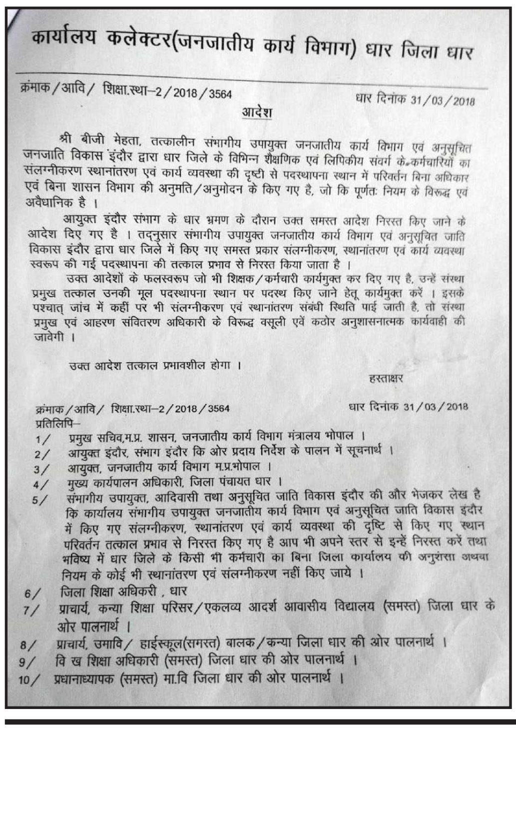

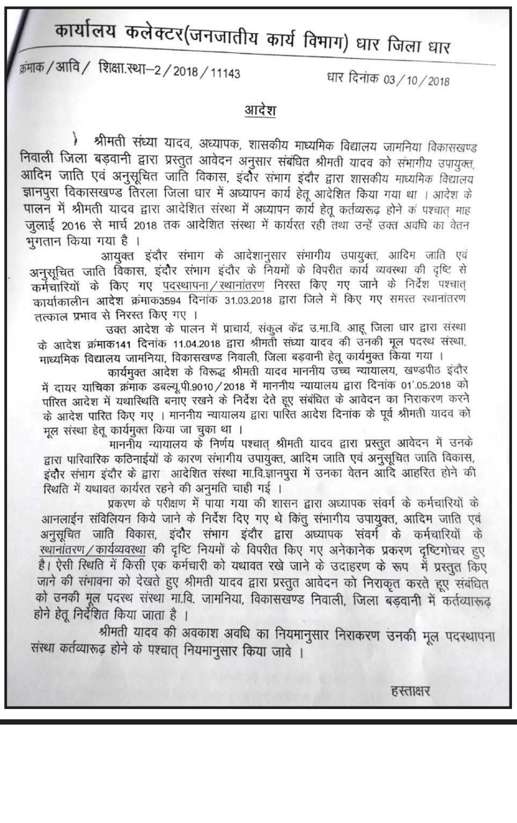

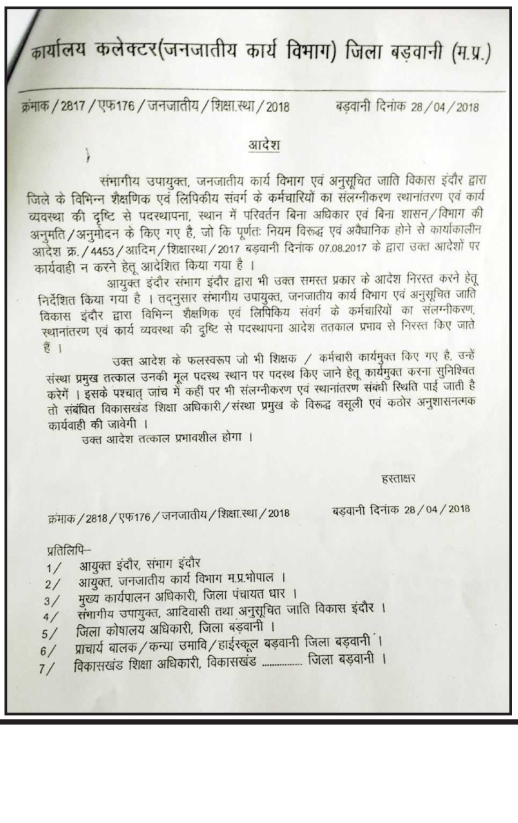

छात्रावासों में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले नाश्ते भोजन के स्तरीय मात्रा और गुणवत्ता नीचे से लेकर न्यूनतम स्तर का खाद्य पदार्थ दूध आदि आपूर्ति कर उसमें भी 25 से 40% तक की कमाई की जाती है। इसीलिए सभी जिलों में आदिवासी बालक बालिका माध्यमिक उच्चतर एवं महाविद्यालयीन छात्रावासों में अधीक्षक बनने के लिए न केवल मोटा पैसा खिलाया जाता है। वरन मासिक चंदा भी जिलों के सहायक आयुक्तों संभाग के उपायुक्तों से लेकर आयुक्त पीएस मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचता है। यही कारण है की इंदौर के आदिवासी 6 जिलों में सहायक आयुक्त बनने के लिए मोटा पैसा खर्च कर पूर्व से ही दोषी अधिकारियों को वहां पदस्थ कर दिया जाता है। धार में ही सन 2002 में पदस्थ बीजी मेहता जो एक सांख्यिकीय अधिकारी था वर्षों तक सहायक आयुक्त बनाकर पदस्थ रहा और अरबो रुपए की हेर फेर के सैकड़ो शिकायतें होने के बाद में भी उसको नहीं हटाया गया।

बाद में वही बीजी मेहता मोटा पैसा खर्च कर इंदौर संभाग के ही उपयुक्त बन गए और जाते-जाते रिटायरमेंट से पहले उन्होंने 5-5 लाख रूपए लेकर लगभग 100 से ज्यादा अटैचमेंट धार के स्कूलों में कर दिए। इसमें एक अटैचमेंट संध्या यादव का भी था जो धार के ही भाजपा के नेता की पत्नी है। और उनको भी इसी प्रकार कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का का अधीक्षक बना दिया गया।

जब यह शिकायत इंदौर के तत्कालीन संभाग आयुक्त संजय दुबे को मिली तो उन्होंने सारे अटैचमेंट रद्द कर दिये। कदम सर इंदौर-धार का बड़वानी के जिला कलेक्टरों ने भी इस प्रकार के सभी अटैचमेंट जो धार के स्कूलों में किए गए थे और धार के स्कूलों के शिक्षकों को इंदौर केआदिम जाति के स्कूलों में उनकी मर्जी के हिसाब

से पैसा लेकर भेज दिया गया था परंतु वेतन उनका मूल विभाग से ही निकल रहा था।

वर्तमान में धार में पदस्थ सहायक आयुक्त आदिम जाति बृजकांत शुक्ला ने खालवा जनपद पंचायत जिला खंडवा रहते हुए 50 लाख 40000 रुपए का तेजस्वी लोक कल्याण एवं शोध संस्थान को बिना किसी कार्य संबंधी पत्रों के निष्पादन के बिना भुगतान कर गवन किया था जिसके अंतर्गत उनको आरोप पत्र क्रमांक 16569 भी दिया गया और निलंबित करने के साथ उनसे लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15 9 2013 द्वारा 50 लाख 40000 में से कुर्क राशि 3 लाख 18119 काम कर 47लाख रु. 21881 की वसूली भी की जाने वह संचय प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रुकने का भी आदेश दिए जाने के बावजूद यह ब्रजकांत शुक्ला अभी तक लूटो और लुटाओ के दम पर शान से सहायक आयुक्त के पद पर धार मैं पदस्थ है। जबकि इतने बड़े गवन के आरोप में उसे पुनः पदोवनति करके इंदौर संभाग से दूर कहीं शहडोल सिंगरौली जैसे अन्य जिलों में पदस्थ किया जाना चाहिए था।

यही कारण है धार के साथ इंदौर संभाग के 6 जिले अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, जबलपुर संभाग के छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, उज्जैन, उज्जैन संभाग के रतलाम जिले का सैलाना तहसील व ब्लॉक नर्मदापुरम, बैतूल, शहडोल, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, चंबल संभाग का श्योपुर, रीवा संभाग का सिंगरौली और सीधी आदि 26 जिलों के सहायक आयुक्त न केवल आदिम जाति स्कूलों महाविद्यालयों व उनके छात्रावासों, क्रीड़ागनों जिलों के विकासखंडों व ग्रामीण क्षेत्रों के विकास मैं विभिन्न योजनाओं में हजारों करोड रु की खरीदी निर्माण आदि, छात्रवृत्ति वितरणके विभिन्न माध्यमों सिनर्जी स्कूलों कोचिंग संस्थानों शिक्षण केंद्रों में 20 सेकंड करोड़ का भ्रष्टाचार करते हैं और यह हालत हर आदिम जातीय जिले के सहायक आयुक्त और जिला संयोजकों द्वारा हर स्तर पर खरीदी वितरण संलग्नीकारण स्थानांतरण पदस्थी करके सैकड़ो करोड़ हजम करते हैं और जिसकी बंदर बाट का पैसा छात्रावासों के अद्यीक्षकों से लेकर जिला कार्यालय उसे जिलों के कलेक्टर संभाग आयुक्त आदिम जाति उपयुक्त आयुक्त प्रधान सचिव मंत्री और मुख्यमंत्री तक बढ़ता रहता है इसलिए सब आंख बच कर ऐसे सारे भ्रष्टाचारों को दबाकर अपना हिस्सा हजम करते रहते हैं जो की जनता से पेट्रोल डीजल गैस के साथ 1500 से ज्यादा वस्तुओं पर जीएसटी में लूटा गया धन होता है आखिर नियम कानून क्या लूट और कमाई के साधन ही बन के रहेंगे या उनके अनुसार कार्रवाई कार भ्रष्टों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य एवं औषधि विभाग में नमूनों की जांच के नाम मोटी कमाई

पेज 8 का शेष

एनएबीएल गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से मान्यता सेवाएं प्रदान करता है। ये सेवाएँ भारत और क्षेत्र के अन्य देशों में चिकित्सा और अंशांकन प्रयोगशालाओं, दक्षता परीक्षण प्रदाताओं और संदर्भ सामग्री उत्पादकों सहित सभी परीक्षणों के लिए सुलभ हैं, चाहे आवेदक सीएबी का आकार या किसी एसोसिएशन या समूह की सदस्यता या पहले से ही सीएबी की संख्या कुछ भी हो। एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त। लागू शुल्क के लिए कृपया NABL 100A 'सामान्य सूचना विवरणिका' देखें।

वे अनुशासन और समूह जिनके लिए संबंधित क्षेत्रों में मान्यता सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, सूचीबद्ध हैं -

एनएबीएल 120 'परीक्षण और अंशांकन क्षेत्र में उत्पाद समूहों के वर्गीकरण के लिए मार्गदर्शन'

एनएबीएल 112 'चिकित्सा प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन के लिए विशिष्ट मानदंड'

एनएबीएल 180 'प्रवीणता परीक्षण प्रदाताओं (पीटीपी) के लिए आवेदन पत्र'

एनएबीएल 190 'संदर्भ सामग्री उत्पादक प्रत्यायन (आरएमपी) के लिए आवेदन पत्र'

एनएबीएल सीएबी, मूल्यांकनकर्ताओं और अपने स्वयं के उपयोग के लिए दस्तावेज़ प्रकाशित करता है। एनएबीएल से बाहर के व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए बनाए गए सभी एनएबीएल दस्तावेजों को एनएबीएल की वेबसाइट www.nabl-india.org >>publications>> NABL दस्तावेजों पर निःशुल्क देखा जा सकता है।

परंतु 90% में इन एनएबीएल लैबोरेट्रीज में उच्च भौतिक रसायन और जीव विज्ञान शिक्षित समझदार अधिकारियों कर्मचारियों वैज्ञानिकों काउच्च वेतन के कारणअभाव होता है जैसा कि हमने कोरोना काल में देखा था कि अधिकांश पैथोलॉजिकल लेब बीमारियों के नाम पर मोटी कमाई करने के बाद में भी जब उन प्रयोगशाला में जाकर देखा तो ना तो वहां पैथोलॉजिकल एमबीबीएस एमडी डॉक्टर था ना ही कोई उच्च शिक्षित माइक्रो बायोलॉजी का वैज्ञानिक कल तापमान पर सारे के सारे लड़के आठवीं दसवीं पास या फेलबिना साधन के कागजों पर मनचाही रिपोर्ट लिखकर डॉक्टर से हस्ताक्षर करवा कर मोटा पैसा वसूल कर कोरोना की जांचके प्रमाण पत्र बांट रहे थे। वे सभी पैथ लेब भी एनएबीएल संस्थान से मान्यता प्राप्त थी। यह संस्था भी मोटा पैसा लेकर मान्यता प्राप्त की सर्टिफिकेट दे देती है। जिन में उच्च शिक्षित मानव संसाधन का अभाव होने के साथ-साथ प्रयोगशाला की जांच में लगने वाले अन्य जांच उपकरणों, मशीनों, रसायनों आदि तक का अभाव होता है परंतु वे अधिकांश करोड़ों की

प्रयोगशालाएं बड़े-बड़े अधिकारियों और नेताओं के रिश्तेदारों की होती हैं। इसलिए उनको मान्यता दे दी जाती है। जोकि खाद्य फसलों वस्तुओं औषधियों के एक तो नमूनों के सही विश्लेषण नहीं कर पाती, तो दूसरी तरफ वहां सारा खेल पैसे का चलता है पैसा खर्च करो

World Health Organization

और जैसे चाहे इच्छा के अनुकूल प्रमाण पत्र बनवा लो और वे प्रमाण पत्र न्यायालय में भी उचित साक्ष्य के रूप में मंजूर किए जाने की व्यवस्था है चाहे वह कितने भी मानव स्वास्थ्य के लिए घातक क्यों ना हो? तो दूसरी तरफ यह सारा खेल खाद्य एवं औषधि विभाग में बैठे खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं औषधि निरीक्षक जिनके नमूने लिए हैं उनको मोटा पैसा मिल जाने पर और दलाली सिद्ध हो जाने पर वह स्वयं ही प्रयोगशालाओं से खाद्य औषधि के प्रमाण पत्र लेकर उत्पादक को बचाने और फसाने का खेल करते हैं। इंदौर में ही बैठे खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी रघुवंशी इस खेल में पारंगत है और आपको याद होगा? तत्कालीन कलेक्टर मनीष सिंह ने मनीष स्वामी को निलंबित कर अपने कार्यालय में ही संलग्न कर लिया थाऔर बाद में अनेक को शिकायतें होने पर उसने स्वयं ही मोटा पैसा खर्च कर उज्जैन स्थानांतरण ले लिया था आप पुनः मोटा पैसा खर्च कर चुनाव के पहले ही वह इंदौर आ चुका है और फिर वही छोटे-मोटे व्यापारियों उद्योगों विक्रेताओं के नमूने लेकर मोटे कमीशन पर मध्य प्रदेश के बाहर भी जिसमें महाराष्ट्र के पुणे मुंबई नागपुरवी गुजरात के सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा आदि शहरों की एनएबीएल पंजीकृत प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। जिनमें से बहुतों की ऑनलाइन रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है अब विक्रेता उत्पादक चाहे तो अपने उसे माल की जांच दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद की अन्य प्रयोगशाला और करवा सकता है इस प्रकार से यथार्थ में व्यापारी के सांसद विभाग के लोग भी बचाने को बचाने के खेल में मोटा पैसा ऐंठ लेता है व्यापारियों से, मनीष स्वामी और विश्व घातक संगठन के इशारे पर नाचने वाले सरकारी गिरोहों ने लिए थे। उसमें 30 से 40% नमूने भोपाल स्टेट राजकीय प्रयोगशाला में भी भेजे गए जबकि वहां कोई भी बजट नोटिफाईड सरकारी विश्लेषक वर्षों से नहीं है। कनिष्ठ विश्लेषकों से काम करवा कर रिपोर्ट जारी की जा रही है। यही हाल इंदौर के साथ उज्जैन दीवार धार भोपाल ग्वालियर आदि पूरे 52 जिलों का है। यहां बैठे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को मोटी कमाई करके भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजने के साथ जिलों के कलेक्टर सीएम एचओ को भी महीना देना पड़ता है। जैसा कि खाद्य सुरक्षा और मानव अधिनियम 2006 में व्यवस्था की गई है कि सभी छोटे व्यापारियों को दुकानदार को बाजरो मंदिरों को खत्म करने के लिए लगातार उनके नमूने लिए जाते रहे जबकि दूसरी तरफ बहुराष्ट्रीय कंपनियों यथा वॉलमार्ट अमेजॉन युनिलीवर आईटीसी आदि मोदी के पूंजीपति मित्रों दिन में अडानी अंबानी टाटा बिरला मित्तल आदि के द्वारा किसानों से 10 20% के खरीदे हुए माल को100 से 200% की कीमत पर बेचने के लिए सभी प्रकार के अनाजों दलहन तिलहन तेल बिस्किट आटा दालें मसाले सब्जियां के साथ सभी खाद्य पदार्थों फसलों मैं कीटनाशक व प्रशीतक या प्रिजर्वेटिव्स मिला पैक कर बेंचा जा रहा है। जोकि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के खाद्य नियंत्रक द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 96.4% पैकेज्ड फूडविभिन्न कीटनाशकों और प्रिजर्वेटिव रसायन मिलने के कारण स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक घातक व अनेकों गंभीर बीमारियां उत्पन्न करने वाला होता है। इस संबंध में हम नमक को ही देखे तो हमारे देश में जो टाटा द्वारा 2 करोड रुपए खर्च कर बनवाया गया 1971 का आयोडीन साल्ट एक्ट के अंतर्गत जो आयोडीन नमक बेंचा जा रहा है। जिसके विरुद्ध भाजपा ने 1998 तक लगातार देश में आंदोलन किया जो की देश में ब्रेन हेमरेज हृदय यकृत प्लीहा की निष्क्रियता व अकर्मण्यता का कारण बन बीमारियों का कारण है। भाजपा की सरकार आने पर भी भाजपा ने उस नमक को बंद नहीं किया।

आखिर खाद्य विभाग के पूरे 52 जिलों में बैठे घोर भ्रष्ट जालसाज हरामखोर 200 से ज्यादा खाद्य निरीक्षक सह खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल में जाकर आखिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पैकेज्ड फूड के नमूने क्यों नहीं लेते। क्योंकि उन सब का वहां से महीना बंधा हुआ है। और उनका स्पष्ट निर्देश हैं कि छोटे व्यापारियों उद्योगों दुकान दारों बाजारों मंडियों को खत्म करने के लिए इनको कानूनी जाल में उलझा कर खत्म किया जाए। ताकि यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शॉपिंग मॉल और उनका बिकने वाला माल के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों निगम आयुक्तों कलेक्टर कमिश्नर पुलिस कमिश्नर से लेकर स्वास्थ्य मुख्य व प्रधानमंत्री मंत्री राज्यों के व केन्द्र सरकार के सबको अरबो रुपए का धन उनके वेतन व पद के हिसाब से जब तक नौकरी या पद पर रहेंगे मिलता रहेगा। इसी कारण अब चूंकि देश के तीन बड़े राज्यों में इवीएम की जालसाजी से भेड़िया झुंड पार्टी की सरकार आ चुकी है। और वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कठपुतली होने के साथ-साथ अपने पूंजीपति मित्रों के लिए पुनः कोरोना का तांडव कर यही खेल दोहराना चाहती है। ताकि सारे छोटे बाजार मंडियां दुकानदार पद मार्गों और ठेले पर सब्जी बेचने व अन्य सामग्री बेचने वालों को सफाई व कानून के माध्यम से आसानी से घर पर बैठाकर इन बहुराष्ट्रीय कंपनी की शॉपिंग मॉल का मोटा फायदा करवाया जा सके। और उसके लिए सरकार ने तत्काल में आप देखिए सफाई के नाम पर किस प्रकार से पूरे देश के अंदर फुटपाथ सफाई के नाम पर ठेले और पग मार्गों पर फल फूल सब्जी बेचने सामग्री बेचने वालों को हटाने का षड़यंत्र किया जा रहा है। यह यथार्थ में सब कुछ विश्व घातक संगठन के इशारे पर किया जा रहा है। और यह सारे खाद्य एवं औषधि निरीक्षक उसकी कठपुतली बन सभी छोटों को खत्म करना चाहते हैं। जहां तक औषधि निरीक्षकों का सवाल है। तो उन्हें भी चूंकि सभी थूक रक्त मल मूत्र वीर्य रज विस्टा आदि की पैथ लेब के साथ-साथ अधिकांश निजी चिकित्सालयों एवं एलोपैथिक औषधि विक्रेताओं ब्लड बैंकों से महीना मिलता है। इसलिए वे किसी भी मेडिकल स्टोर ब्लड बैंक पैथोलॉजी लेब या सरकारी व निजी चिकित्सालय में उनके यहां उपयोग की जा रही औषधीयां इंजेक्शन सर्जिकल उपकरणों आदि कीजांच नहीं करते हैं? क्योंकि सबको सबसे महीना मिलता है इसलिए यह हरामखोर खाद्य एवं औषधि निरीक्षक और उनके कार्यालय सूचना के अधिकार में जानकारी देने के नाम पर भारी नौटंकी करते हैं। और उज्जैन में बैठा औषधि निरीक्षक कुशवाहा घोर भ्रष्ट होने के साथ भारी बदतमीज है। जिसे 3 साल से ज्यादा समय हो जाने के कारण तत्काल में रीवा बालाघाट, भिंड, मुरैना स्थानांतरित किया जाना चाहिए ताकि इसकी यह ऐंठ व बत्तमीजियां वहां की जनता सुधार सके।

सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर भारी आवेदकों से बदतमीजी के साथ व्यवहार करता है। चूंकि सभी सीएम एचओ को इन खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों से अपने पद के व अपीलीय अधिकारी होने के कारण मोटा महीना वसूली करने व मिलने से वह अपने अंतर्गत कार्य कर रहे। क्योंकि वह स्वयं उनके उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन भी होता है बचाता है। जबकि एमपी एफडीए की साइट खुलती ही नहीं है। और ना ही उस पर17 के साथ जोड़े गए 8, कुल 25 बिंदुओं की जानकारी इस हरामखोर जालसाजों के भ्रस्ट विभाग ने भोपाल के मुख्यालय से ही अभी तक अपलोड नहीं की है। क्योंकि सरकार की खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला मैं ना तो पूरा स्टाफ है ना वरिष्ठ अनुभवी विश्लेषक, फिर भी नैनो की जांच वर्षों से चल रही है उसे पर कार्रवाई भी हो रही है परंतु सारा खेल जिलों में बैठे वरिष्ठ खाद्य एवं औषधि निरीक्षक धन ले दे कर वर्षों से बचाने और फंसाने का खेल कर मोटी कमाई करते आ रहे हैं।

साप्ताहिक समय माया

चारों तरफ हर विभाग में पूरी सफाई और बदलाव की जरूरत

भारतीय प्रताड़ना सेवा के पीएस घोर धूर्त भ्रष्टों के बदलें विभाग

दीपाली रस्तोगी, राजेश राजौरा, सुलेमान, एसएन मिश्रा वर्षों से कुंडली मारे कर रहे राजस्व चौपट

प्रदेश सरकार पूर्व से ही रुपए 300 लाख 50 हजार करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है और फिर आते ही रु.2000 करोड़ का कर्ज और लिया जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है जबकि 10 लाख कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी संविदा और आउटसोर्स पर काम कर जिन्हें मात्र 8 से रु.10000 वेतन दिया जा रहा है। दूसरी तरफ पेट्रोल, डीजल, गैस व शराब पर अभी भी वेट लग रहा है और पेट्रोल डीजल गैस पर 40% तक और शराब पर तो लगभग 150 से 200% तक का टैक्स वसूल किया जा रहा है। सभी शासकीय विभागों में मात्र 20 से 30% स्टाफ रह गया है तो उनका वेतन भी बच रहा है बेशक जो अपने मित्रों के फायदे के लिए शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर और भोपाल में 25-25000 करोड रुपए की जो मेट्रो ट्रेन का मोटे कमीशन का खेला किया। अनावश्यक रूप से प्रदेश भर में जो ओवर ब्रिज बनकर मोटे कमीशन के लिए खेल किया जा रहा है उसको भी तत्काल रुक जाना चाहिए बड़ी परियोजनाओं में जो जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी में लगभग एक से डेढ़ लाख करोड रुपए की चल रही है उनमें से जल संसाधन विभाग की योजनाओं को लंबित किया जा सकता है जहां तक नर्मदा घाटी का सवाल है तो उसकी समय सीमा अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। उसके पूर्व आपको 18.25 एमसीएम नर्मदा के अपने हिस्से के पानी का उपयोग बांध बना नहरें पाइप लाइन बिछा कर करना अति आवश्यक है। अन्यथा बचा हुआ पानी गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान उपयोग में लेने के अधिकारी हो जाएंगे। परंतु सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता इस बात की है की मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग प्रदेश भर में बन रही वृहद मध्यम और लघु उद्वहन जल परियोजनाओं के साथ अन्य सभी परियोजनाओं की बारीकी से समीक्षा करें काफी कुछ पैसा बचाने के साथ-साथ जितना पैसा लग चुका हैउन सब का सबसे पहले उत्पादक उपयोग करें अर्थात सबसे पहले नहरों में पानी चलाएं और वह पानी किसानों को वर्षा के अतिरिक्त वर्ष भर नियमित रूप से मिलता रहेगा तो कृषि की फसलें वर्ष भर मिल सकती है। इससे प्रदेश और देश मैं कृषि फसलों की बारह मासी उत्पादकता बढ़ाने से किसानों की आय बढ़ने पर उनकी क्रय शक्ति बढ़ने से खाद्य वस्तुओं से संबंधित सभी प्रकार के व्यवसाय को भी पर्याप्त रोजगार और लाभ मिलता रहेगा। इससे सरकार को करों के माध्यम से आय बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान में प्रधान सचिव मध्य प्रदेश वाणिज्य कर आबकारी व पंजीयन महिला बाल विकास की दीपाली रस्तोगी काफी लंबे समय से कुंडली मारे बैठी हुई है। और वाणिज्य कर विभाग को बर्बाद करने पर तुली है। तत्काल प्रभाव से उनको हटाकर प्रदेश के सभी 40 से ज्यादा अंतर राज्यीय वाणिज्य कर नाकों पर पुनः चौकियां खोल प्रदेश से बाहर जाने वाले और प्रदेश में आने वाले माल की बारीकी से जांच कर कर छोरी को रोका जाना चाहिए दूसरी तरफ वाणिज्य कर विभाग की 6 से ज्यादा एंटी विजन विंग जो पिछले 2 साल से केवल कार्यालय इन कार्य में व्यस्त हैं उनको खुले में माल भाग पकड़ने की छूट दी जानी चाहिए ताकि वह मालवा आंखों से प्रदेश में आ रहे और प्रदेश से बाहर जा रहे माल पर जांच कर धारा 6871 के अंतर्गत कर शास्ती अधिरोपित कर एक तरफ ट्रांसपोर्टरों में बिना बिल बिल्टी या एक ही बिल्टी पर दो-तीन तीन बार माल लाने ले जाने की जालसाजियां रोकी जा सकें। ताकि प्रदेश का राजस्व बढ़ाया जा सके प्रदेश के राजस्व बढ़ाने के मामले में आबकारी और पंजीयन भी भारी जालसाजियां कर और राजस्व को क्षति पहुंचाते हैं उनके ऊपर भी कड़ी रंगरानी होनी चाहिए जितनी भी फैक्ट्री से देसी विदेशी शराब बन रही है उन सबके ऊपर भी कड़ी निगरानी रख एक ही बिल्टी पर तीन-तीन चार ट्रक शराब का परिवहन कर राजस्ब हानि पहुंचाई जाती है। पंजीयन विभाग में बैठे हुए पूरे प्रदेश भर में दो सौ से ज्यादा उपपंजीयकों को अधिकांश उप पंजीयक वर्षों से एक ही स्थान पर जमे रहकर दलालों के हाथ की कठपुतली बन एक तरफ मोटी कमाई करते हैं। तो दूसरी तरफ भारी राजस्व की मोटी हानि करते हैं। इंदौर में ही अकेले 13 से ज्यादा उपपंजीयक में से अधिकांश वर्षों से एक ही स्थान पर कुंडली मारे बैठे हैं। जिन्हें तत्काल बदल जाना चाहिए। ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माल पर जो कि गांव की दुकानों से लेकर शहरों की शॉपिंग मॉल तक में भारी मात्रा में बिकता है भारी टैक्स चोरी की जाती हैजिन्हें तत्काल पकड़ा जाना चाहिए। वाणिज्य कर आयुक्त लोकेश जाटव को भी बदला जाना चाहिए। क्योंकि अभी विभागीय काम को फैलाने और समेटने में ही स्वयं वह पूरे स्टाफ कोव्यस्त रखते हैं। जिससे राजस्व की भारी हानि हो रही है। क्योंकि राज्य को चलाने के लिए आए बढ़ाना ज्यादा जरूरी है अपेक्षाकृत कर्ज लेकर क्योंकि कर्ज को चुकाना भी पड़ेगा ब्याज के साथ और कब तक कर्ज लेकर सट्टा चलाई जा सकती है इस बात को नए मुख्यमंत्री को समझना होगा। मनीष सिंह, सुलेमान, राजेश राजौरा, एसएन मिश्रा के वर्षों से एक ही विभागों में बैठकर मोटी कमाई और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनके ही नहीं वरन् सारे कलेक्टर, कमिश्नर, आयुक्त सचिव, प्रधान सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद संभाले हुए सारे आइएएस के 6 महीने की कॉल डिटेल निकलवा कर मालूम किया जाना चाहिए कि उन्होंने कितने हजार करोड़ देश और विदेश में निवेशित कर रखा है। ये जिस विभाग में भी रहे वहां भारी भ्रष्टाचार का तांडव कर धनार्जन किया। कुछ पुराने अधिकारियों पर जो जांचें लंबित है उन पर भी फाइलें खुलकर लोकायुक्त आर्थिक कन्वेंशन ब्यूरो को कार्रवाई करने मुकदमा चलाने की तत्काल आज्ञा दी जानी चाहिए ताकि दूसरे आईएएस अधिकारियों को सबक मिले और वह भ्रष्टाचार को न्यूनतम कर प्रदेश में सार्वजनिक योजनाओं में खर्च किए जा रहे धान का पूरा फायदा जनता को मिल सके और उसे उत्पादकता बढ़ सके। इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। **(शेष पेज 5 पर)**

देश प्रदेश का पूरा खाद्य एवं औषधि विभाग विश्व स्वास्थ्य घातक संगठन की कठपुतली

खाद्य एवं औषधि विभाग में नमूनों की जांच के नाम मोटी कमाई

90% एनएबीएल लैब्स में पर्याप्त साधन ही नहीं, करती हैं फर्जीवाड़े से मोटी कमाई

विश्व स्वास्थ्य घातक संगठन एवं विश्व घातक व्यापार संगठन दोनों ही अमेरिकी संगठन जो कि अमेरिकी यूरोपियन, वॉलमार्ट, अमेजॉन, युनिलीवर जैसी अनेकों शैलेकारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के छल कपट भ्रष्टाचार जालसाजियों से अन्य राष्ट्रों के प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधनों पर कब्जा करने के लिए वहां की सरकारों को वित्तीय सहायता व कर्ज दे उलझाकर कानून बनवाती है और अपना माल सेवाये बेंचने के लिए से व्यवसाय संवर्धन के लिए ही चलाई जाती हैं। उन्होंने ही सरकारी नियमों कानून और चंगुलों से बचने के लिए हमारे देश की कठपुतली सरकार पर निकॉन जालसाजी पूर्ण नियम कानून ठोकने के साथ भारत में भी और राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोध प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना कर जो की नेशनल एक्रेडीशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेट्रीज यह भारतीय गुणवत्ता परिषद अर्थात एक क्वालिटी काउंसिल आफ इंडिया केअंतर्गत चलता है। जिसके प्रस्तावना में निम्नानुसार लिखा गया है।

परिचय

परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) एक मान्यता निकाय है, इसकी मान्यता प्रणाली आईएसओ / आईईसी 17011 के अनुसार स्थापित की गई है। 'अनुरूपता मूल्यांकन - अनुरूपता मूल्यांकन निकायों को मान्यता देने वाले प्रत्यायन निकायों के लिए आवश्यकताएँ।' एनएबीएल इन्हें स्वैच्छिक मान्यता सेवाएं प्रदान करता है:

आईएसओ/आईईसी 17025 के अनुसार परीक्षण प्रयोगशालाएँ 'परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं की क्षमता के लिए सामान्य आवश्यकताएँ'

आईएसओ/आईईसी 17025 के अनुसार अंशांकन प्रयोगशालाएँ 'परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं की क्षमता के लिए सामान्य आवश्यकताएँ'

आईएसओ 15189 के अनुसार चिकित्सा परीक्षण प्रयोगशालाएँ 'चिकित्सा प्रयोगशालाएँ - गुणवत्ता और क्षमता के लिए आवश्यकताएँ'

आईएसओ/आईईसी 17043 के अनुसार प्रवीणता परीक्षण प्रदाता (पीटीपी) 'अनुरूपता मूल्यांकन - दक्षता परीक्षण के लिए सामान्य आवश्यकताएं' और

आईएसओ 17034 के अनुसार संदर्भ सामग्री उत्पादक (आरएमपी) 'संदर्भ सामग्री उत्पादकों की क्षमता के लिए सामान्य आवश्यकताएं'।

एनएबीएल परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं (आईएसओ/आईईसी 17025), चिकित्सा परीक्षण प्रयोगशालाओं (आईएसओ 15189), प्रवीणता परीक्षण प्रदाताओं (पीटीपी) (आईएसओ/आईईसी 17043) की मान्यता के लिए आईएलएसी के साथ-साथ एपीएसी का पारस्परिक मान्यता व्यवस्था (एमआरए) हस्ताक्षरकर्ता है। और संदर्भ सामग्री उत्पादक (आरएमपी)।

ऐसा एमआरए व्यापार में तकनीकी बाधा को कम करता है और उन देशों के बीच परीक्षण/अंशांकन परिणामों की स्वीकृति की सुविधा प्रदान करता है जिनका एमआरए भागीदार प्रतिनिधित्व करते हैं।

एनएबीएल की स्थापना सरकार, उद्योग संघों और उद्योग को सामान्य रूप से अनुरूपता मूल्यांकन निकाय की मान्यता की एक योजना प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है जिसमें चिकित्सा और अंशांकन प्रयोगशालाओं, दक्षता परीक्षण प्रदाताओं और संदर्भ सामग्री उत्पादकों सहित परीक्षण की तकनीकी क्षमता का तीसरे पक्ष का मूल्यांकन शामिल है। प्रत्यायन प्रक्रिया का विवरण NABL 100B 'प्रत्यायन प्रक्रिया और प्रक्रिया' में प्रदान किया गया है।

एनएबीएल स्व-वित्तपोषण है और परिचालन लागत और अन्य व्यय को कवर करने के लिए अनुरूपता मूल्यांकन निकायों से शुल्क लेता है।

(शेष पेज 7 पर)

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
संपादकः अजमेरा एस.पी. कुमार, मो. 9425125569, भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958